शैक्षिक मंथन

(द्विभाषी मासिक)

शैक्षिक क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 9 अंक : 10 1 मई, 2017

(वैशाख-ज्येष्ठ, विक्रम संवत् 2074)

संस्थापक संरक्षक
स्व. श्री मुकुन्द कुलकर्णी के.नरहरि

❖

परामर्श
डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल
जगदीश प्रसाद सिंघल

❖

सम्पादक
सन्तोष पाण्डेय

❖

सह सम्पादक
विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी ❑ भरत शर्मा

❖

संपादक मंडल
प्रो. नन्दकिशोर पाण्डेय
डॉ. नाथू लाल सुमन
डॉ. एस.पी. सिंह
डॉ. ओमप्रकाश पारीक

❖

प्रबन्ध सम्पादक
महेन्द्र कपूर

❖

व्यवस्थापक
बजरंग प्रसाद मजेजी

प्रेषण प्रभारी
बसन्त जिन्दल ❑ नौरंग सहाय भारतीय
कार्यालय प्रभारी
आलोक चतुर्वेदी : 9782873467

प्रकाशकीय कार्यालय
82, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग,
जयपुर (राज.) 302001
दूरभाष : 9414040403

दिल्ली ब्यूरो :
शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13,
कृष्णा गली नं.9, मौजपुर, दिल्ली-110053
दूरभाष : 011-22914799

E-mail :
shaikshikmanthan@gmail.com
Visit us at :
www.shaikshikmanthan.com

एक प्रति 20/- वार्षिक शुल्क 200/-
आजीवन (दस वर्ष) 1500/-

पृष्ठ संयोजन : सागर कम्प्यूटर, जयपुर

शैक्षिक मंथन मासिक में प्रकाशित सामग्री से संपादक मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा ❑ प्रो. मधुर मोहन रंगा

भारत को स्वतंत्र हुए 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम अब भी न्यूनतम अधिगम पर अटके हैं। आवश्यकता है कि विशिष्ट कौशलों के विकास की जो बालक को जीवन में स्वावलम्बन व रोजगार दे सकें। जो परिवारों को भविष्य की अनिश्चितताओं की चिंता से मुक्त कर सकें। ऐसे स्रोतों का विकास गाँव-गाँव, चौपाल-चौपाल और घर-घर हो, ताकि ना केवल बालक वरन् प्रौढ भी स्वतः शिक्षा प्राप्त कर सकें, व बच्चों को कर्मठ बनने की प्रेरणा मिले जिससे शिक्षा की अलख घर-घर जगा पाए। शिक्षा के प्रति आस्था उत्पन्न हो।

9

अनुक्रम

4.	वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य में भारतीय शिक्षा	– सन्तोष पाण्डेय
7.	शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक	– विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी
12.	विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रबन्धन आवश्यक	– डॉ. रेखा भट्ट
15.	वर्तमान परिदृश्य और शैक्षिक उपलब्धि	– डॉ. इन्दु बाला अग्रवाल
17.	माध्यमिक शिक्षा का असली चेहरा	– बजरंगी सिंह
19.	लीक से हटकर हो शिक्षा व्यवस्था	– बजरंग प्रसाद मजेजी
21.	Higher education for uplifting rural...	– Vipul Somani
32.	भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण	– डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि'
35.	डा.अम्बेडकर के जीवन के अनछुए प्रसंग	– सीताराम व्यास
37.	क्या परीक्षा से ही बच्चों का आकलन सम्भव है	– अशोक चतुर्वेदी एवं विनित जोशी
39.	पुण्य स्मरण	
42.	गतिविधि	

Viswa Guru Bharat : Educating the world

❑ Dr. TS Girishkumar

To become Viswa Guru, Bharat has to give the world what they don't have, and what we have in plenty. That shall be original Bharatiya knowledge for the world. We know that all others already have what may be known as empirical scientific knowledge, and we also know that no one has the knowledge of the transcendental, spirituality and Sanskriti as Bharat has. Precisely this is what we should be providing the world with.

27

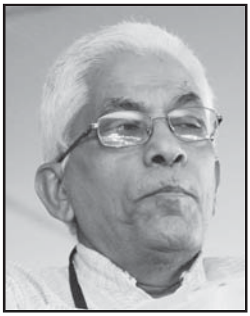

शिक्षा मनुष्य को अपनी क्षमताओं को पूर्णतः निखारने का अवसर प्रदान करती है। इसमें छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था का बड़ा योग है। यह विवाद का विषय बन चुका है कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली श्रेष्ठ है अथवा सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अथवा दोनों का समन्वित उपयोग। भारत में इनके अनुभव कोई सुखद नहीं रहे हैं। वार्षिक सार्वजनिक परीक्षाओं के स्थान पर सीमित सार्वजनिक परीक्षा तथा सतत् व व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाने के कोई सार्थक परिणाम नहीं आने से अब पुनः वार्षिक सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अपनाने पर बल दिया जा रहा है। परन्तु प्रश्न चिह्न अभी भी विद्यमान है कि गुणवत्तापूर्ण व वैश्विक मानकों के अनुरूप परिणाम देने वाली माध्यमिक शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य में भारतीय शिक्षा

❑ सन्तोष पाण्डेय

संपादकीय

भारत की शिक्षा व्यवस्था विश्व की सर्वाधिक विकसित एवं संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। देश में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, तकनीकी, व्यावसायिक, विधिक, शिक्षक प्रशिक्षण व प्रोफेशनल ही नहीं अत्याधुनिक विधाओं के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। सामान्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ विभिन्न विशेषज्ञताओं के विश्वविद्यालय भी विद्यमान हैं। ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिये आवश्यक स्कूलों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की संख्या में अनवरत वृद्धि हो रही है। समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकारें सभी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था करने में जुटी हैं। शिक्षा के तेज गति से प्रसार तथा विकास के लिये निजी उद्यम को भी शिक्षा में भाग लेने का अवसर दिया गया है। शिक्षा के विकास व इसे समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने की दृष्टि से अनेक शिक्षा आयोग व विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया है जिनकी अनुशंषाओं के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को ढालने का प्रयास हो रहा है। शिक्षाविदों व शिक्षा-विशेषज्ञों की अनुशंषाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। समाज में शिक्षा की महती आवश्यकता को दृष्टिगत कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनायी गई है व निर्धारित उद्देश्यों व लक्ष्य प्राप्ति पर बल दिया गया है।

आज की वैश्विक शिक्षा व्यवस्था के साथ कदमताल करते हुये अपेक्षित कदम उठाये जा रहे हैं। वैश्विक शैक्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत भारत में भी मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत व संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के ध्येय से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के अन्तर्गत स्कूलों में शत् प्रतिशत् नामांकन का लक्ष्य निर्धारित करते हुये सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि का परिणाम है कि देश के लगभग सभी भागों में सभी वर्गों को प्राथमिक शिक्षा का लाभ मिल रहा है। शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल करने की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। सभी को शिक्षा का अवसर कानूनी रूप से मिले इस दृष्टि से 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे व बच्चियों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था 2009 से प्रारम्भ की गई है। इस वैधानिक व्यवस्था से निःसंदेह 6-14 के

आयु वर्ग को शिक्षा की सुविधा मिली है। समाज का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में भारी बदलाव आया है। आज प्रत्येक अभिभावक अनुभव करता है कि बच्चों को शिक्षा दिलाकर ही गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक व सामाजिक असमानता से मुक्ति संभव है। आज अभिभावक मात्र शिक्षा ही नहीं दिलाना चाहता है वरन वह श्रेष्ठतम शिक्षा उपलब्ध कराना चाहता है। इस हेतु वह सभी प्रकार के त्याग के लिये तत्पर रहता है। समाज में शिक्षा की जितनी भूख जाग्रत हुई है, उसे संभवत: सरकारें अकेले उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाती है, जिससे निजी उद्यम के लिये शिक्षा क्षेत्र को खोला गया है। निजी उद्यम ने इस अवसर को हाथों हाथ लेकर एक स्वर्णिम लाभदायक उद्योग में बदल दिया है।

शिक्षा राज्य व केन्द्र सरकारों का उत्तरदायित्व है। सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना राज्यों का वैधानिक दायित्व है, जिसका निर्वहन करने में सरकारें सफल नहीं हो पा रही हैं। निजी उद्यम ने नि:संदेह शिक्षा व गुणवत्ता वाली शिक्षा की व्यवस्था में तो योग दिया है, परन्तु शिक्षा के बड़े क्षेत्र पर, आधिपत्य के लिये राजकीय शिक्षण संस्थानों को द्वितीय श्रेणी शिक्षण संस्थान की धारणा को बलवती बनाया है। सरकारों ने भी कम से कम वित्तीय प्रावधानों के सहारे अधिकतम गाँवों व शहरों को शिक्षा सुविधा प्रदान कर राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास ने सरकारी स्कूलों को जर्जर बनाने में योग दिया है। इन सभी का सम्मिलित परिणाम है शिक्षा के स्तर में गिरावट, अधिगम का निम्न स्तर। प्राथमिक शिक्षा की निम्न गुणवत्ता में शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार पर अत्यधिक जोर देने, आठवीं कक्षा तक किसी को भी अनुत्तीर्ण नहीं करने, अस्पष्ट अधिगम निर्धारण, मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता, अपर्याप्त भौतिक सुविधाओं, शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या शिक्षकों को शिक्षण के बजाय अन्यान्य कार्यों में लगाना, स्थानान्तरण आदि ने योग दिया है। परिणाम है कि प्राथमिक स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाले केन्द्र के स्थान पर मध्याह्न भोजन प्रदान करने वाले केन्द्र बनकर रह गये हैं। अधिगम का निम्न स्तर प्रतिवर्ष सम्पन्न होने वाले शैक्षिक सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है जिसमें छात्र अपनी वर्तमान कक्षा से कई कक्षा नीचे की पुस्तक को पढ़ने, लिखने व साधारण गणित की क्रियाओं को करने में असमर्थ है। यह किसी एक प्रांत की नहीं संपूर्ण देश की समस्या है। पीसा द्वारा आयोजित परीक्षा में देश के श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था वाले राज्यों से गये विद्यार्थियों द्वारा 73 देशों में 72 वाँ स्थान प्राप्त करना, भारतीय शिक्षा पर एक पीड़ादायक टिप्पणी है। आगे ऐसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेकर कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में भारत को देश की शिक्षा व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचाने के लिये कठोर परिश्रम करना होगा। इसमें सभी संबद्ध वर्गों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

माध्यमिक शिक्षा की स्थिति भी प्राथमिक शिक्षा बहुत भिन्न नहीं है। कुछ समय पूर्व तक स्कूलों की सीमित संख्या के कारण शिक्षा का स्तर संतोषजनक रहा, परन्तु शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत 'नोडिटेंशन पालिसी' के कारण छात्र संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। स्कूलों की संख्या का विस्तार तो हुआ परन्तु सुविधायें व शिक्षण व्यवस्था उस अनुपात में नहीं बढ़ी। फलत: यहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता में भारी ह्रास हुआ है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला रखती है। अपेक्षा की जाती है कि इस स्तर पर बालक-बालिकायें ऐसी योग्यता प्राप्त करें जिससे वे अपने भावी जीवन की रूपरेखा तैयार कर सकें तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा में ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकें, जो उनको स्कूली शिक्षा के उपरान्त व्यवसाय चुनने, उसमें आगे का शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने व स्वरोजगार सृजित करने योग्य बनाये। माध्यमिक शिक्षा अभी भी इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने में समर्थ नहीं है।

शिक्षा मनुष्य को अपनी क्षमताओं को पूर्णत: निखारने का अवसर प्रदान करती है। इसमें छात्रों के मूल्यांकन की व्यवस्था का बड़ा योग है। यह विवाद का विषय बन चुका है कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली श्रेष्ठ है अथवा सतत् व व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अथवा दोनों का समन्वित उपयोग। भारत में इनके अनुभव कोई सुखद नहीं रहे हैं। वार्षिक सार्वजनिक परीक्षाओं के स्थान पर सीमित सार्वजनिक परीक्षा तथा सतत् व व्यापक मूल्यांकन व्यवस्था को अपनाने के कोई सार्थक परिणाम नहीं आने से अब पुन: वार्षिक सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली अपनाने पर बल दिया जा रहा है। परन्तु प्रश्न चिह्न अभी भी विद्यमान है कि गुणवत्तापूर्ण व वैश्विक मानकों के अनुरूप परिणाम देने वाली माध्यमिक शिक्षा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार इसके प्रति सजग व सचेष्ट है। माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिये मिशन के रूप में व्यापक कार्यक्रम लागू किये गये हैं। माध्यमिक स्कूलों में भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराई गई है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक सुधार, कौशल विकास कार्यक्रम आदि अपनाए जा रहे हैं। वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकारें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये अधिकाधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कर रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता शिक्षकों के मिशनरी भावना व पूर्ण समर्पण के बिना संभव नहीं हैं। इस हेतु भी प्रयास आवश्यक हैं। भारत का लक्ष्य भी यूएनओ द्वारा निर्धारित दीर्घ व स्थायी विकास के

लक्ष्य के अन्तर्गत 2030 तक ऐसी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है जिसमें सभी बालक-बालिकाएँ प्रभावी उपलब्धि के साथ शिक्षा पूर्ण कर सकें। केन्द्रीय विद्यालयों व नवोदय विद्यालयों जैसे स्कूलों का विस्तार शनैः शनैः किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा को देश के विकास का इंजन कहा जाता है। विश्वविद्यालयों व अन्य शोध संस्थानों में नित नये नवाचार ज्ञान के नये-नये क्षेत्रों के सृजन द्वारा समाज की समस्याओं का हल ढूँढते हैं। देश में योग्य उद्यमियों, प्रशासकों, नीति-निर्धारकों, कुशल व योग्य तकनीशियनों, इंजीनियरों, चिकित्सा विशेषज्ञों व आर्थिक व्यवस्था के संचालन में निष्णात व्यक्ति विकसित उच्च शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम होते हैं। भारत में उच्च शिक्षा दर जो कुछ समय पूर्व 11 प्रतिशत ही थी, वह अब लगभग दो गुनी हो कर विकसित देशों की दर समकक्ष होने जा रही है। उच्च शिक्षा में संख्यात्मक विस्तार से गुणवत्ता बहुत प्रभावित हुई है। सरकारें विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की निरन्तर बढ़ती वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की साधनहीनता उनके विकास को गंभीर क्षति पहुँचा रही है। एक विश्वविद्यालय तब ही पूर्ण कहा जा सकता है जब वह स्वयं की शिक्षण व्यवस्था, शोध व अनुसंधान की सुविधाओं से परिपूर्ण हो और उसके द्वारा सृजित व संचित ज्ञान का लाभ उसके क्षेत्र के संबद्ध महाविद्यालयों को प्राप्त हो सके और उसके कार्य क्षेत्र आने वाली संपूर्ण प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिल सके। यह भारत की उच्च शिक्षा के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। देश के अकादमिक विश्वविद्यालय के साथ बड़ी संख्या में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी व आईआईएससी, जैसी केन्द्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों का व्यापक नेटवर्क है। वोकेशन व प्रोफेशल शिक्षा के विकास, विस्तार का नियमन करने वाली संस्थायें विद्यमान हैं। यूजीसी, एमसीआई जैसी अन्य संस्थायें भी हैं, इस भारी विस्तार के बावजूद कमी खटकती है कि भारत का कोई संस्थान विश्व की रैंकिंग में स्थान नहीं बना पाया, जबकि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, व चीन के संस्थान रैंकिंग पाने में सफल रहते हैं।

हाल ही के वर्षों में कतिपय आई आईटी रैंकिंग में आने लगी एशियायी रैंकिंग में स्थान बनाने लगी हैं। अब सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील हुई है और लक्ष्य तय किया है कि देश में 20 विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों को विकसित किया जायेगा। इन संस्थानों की संपूर्ण वित्तीय व अन्य आवश्यकतायें पूर्ण की जायेगी। यूजीसी को भी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया जिसके अन्तर्गत नैक द्वारा प्रमाणित ग्रेड के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। रूसा से निःसंदेह विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विकास के नये अवसर मिल रहे हैँ। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार किये गये हैं। पदोन्नति को शोध व अनुसंधान से जोड़ा गया है व शोध प्रकाशन पर बल दिया गया है। इस हेतु यूजीसी ने मान्य शोध पत्रिकाओं की सूची तैयार की है? प्रयास है कि भारतीय भाषाओं में प्रकाशित शोध पत्रिकाओं की संख्या बढ़ायी जाय। इस वर्ष उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को प्रेरित करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी कॉलेजों की रैकिंग व्यवस्था लागू की है। अपेक्षा है कि बेहतर वित्तीय सुविधाओं और प्रतियोगिता के आधार पर, उच्च शिक्षा का गुणात्मक विकास होगा और भारत भी वैश्विक उच्च शिक्षा में अपना स्थान बना सकेगा। प्रधान मंत्री ने मन्तव्य व्यवक्त किया है भारत को 2030 तक विश्व के तीन बड़े विज्ञान देश में शामिल कराने के प्रयास किये जायें। उच्च शिक्षा शोध व अनुसंधान के बिना न तो शिक्षण में गुणवत्ता ला सकती है और न ही विकास का वाहक बन सकती है। इस दृष्टि से भारत अभी भी विश्व मानकों बहुत पीछे है। चीन जो भारत से चार दशक पूर्व बहुत पीछे था, आज बहुत आगे है। भारत की तुलना में वहाँ से कई गुणा अधिक पीएच.डी. निकलते हैं। अब भारत में भी पीएच.डी. के लिये कड़े मानक अपनाये जा रहे हैं। अपेक्षा व विश्वास है कि भारतीय उच्च शिक्षा का निकट भविष्य में गुणात्मक सुधार होगा।

आज की वैश्विक व्यवस्था में शिक्षा भी सेवा क्षेत्र की एक बड़ी वस्तु है। प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में सभी देशों से छात्र अन्य देशों में शिक्षा हेतु प्रवास करते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय आय में महत्त्वपूर्ण योग देती है। आज भारत के पास बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षण संस्थान हैं, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता व प्रसिद्धि प्राप्त है? अभी तक भारत ने बड़े पैमाने पर विदेशियों के लिये शिक्षा को नहीं खोला है। अब समय आ गया है जब भारत को विदेशी छात्रों के लिये खोलना चाहिये। यह संभव है कि प्रारंभ में भारत में निकट पड़ौसी देशों व तृतीय विश्व के छात्र शिक्षा बाजार में प्रस्तुत करने से छात्रों-अध्यापकों का ही आवागमन नहीं होगा, वरन नये विचार, नये पाठ्यक्रम व आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों की संरचना व प्रतियोगिता भारतीय शिक्षा के नये क्षितिज खोल सकती है। भारतीय शिक्षा अनेक कमियों के बावजूद शिक्षा, चिकित्सा व टूरिज्म आज बड़े नये क्षेत्र हैं, जिनमें भारत एक बड़ा खिलाड़ी बन सकता है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी भूमिका निभा सकता है। ❑

शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक

❑ विष्णुप्रसाद चतुर्वेदी

निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पीसा परिणाम का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि भारत के बच्चे बुद्धिहीन होते हैं। मेरी दृष्टि से इसे भारतीय शिक्षा प्रशासन की चूक का उदाहरण माना जाना जाहिए। भारत की माध्यमिक शिक्षा की जिन कमियों की ओर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 7 दशक पूर्व ध्यान आकर्षित किया था उसे हम अभी तक दूर नहीं कर सके हैं। माध्यमिक आयोग ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जीवन से कटी है। बिना अनुसंधान के परम्परागत रूप से पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण करने में असफल रही है। केवल कुछ विषयों को रटाने को शिक्षा का पर्याय मान लिया गया है। विदेशी भाषा ज्ञान के निर्माण में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। शिक्षण विधियाँ बच्चों में स्वतन्त्र चिन्तन व पहल करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाती। प्रशासनिक बाधाओं के कारण बच्चे व शिक्षक में आत्मिक संबंध नहीं बन पाते।

10 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा पूर्ण करने वाले विभिन्न देशों के विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल व ज्ञान का तुलनात्मक सर्वेक्षण को ही प्रोग्राम फोर इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट एसेसमेन्ट (पीसा) नाम से जाना जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली इस परीक्षा का आयोजन आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) सचिवालय द्वारा कराया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन प्रति तीन वर्ष में एक बार किया जाता है। वर्तमान में विश्व की लगभग 90 प्रतिशत आर्थिक शक्तियाँ अपने विद्यार्थियों को इस परीक्षा में बैठा कर अपने देश के शिक्षा स्तर का मूल्यांकन कराने लगी है। पीसा सर्वेक्षण में अच्छा स्थान पाना किसी भी देश के लिए सम्मान का विषय होता है। पीसा में प्रथम स्थान प्राप्त कर फिनलैण्ड जैसा छोटा देश शिक्षा का तीर्थ स्थान बन गया है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी शिक्षा क्षेत्र में फिनलैण्ड का लोहा मानने लगा है। विश्व को सभ्यता का पाठ पढ़ाने का दावा करने वाला इंगलैण्ड, चीन के शिक्षकों को अपने यहाँ मार्गदर्शक के रूप में बुलाने लगा है क्योंकि चीन के शंघाई प्रान्त ने पहली ही बार में पीसा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। पीसा में अभी पूर्वी एशिया के देशों–चीन, दक्षिणी कोरिया,जापान आदि का प्रभुत्व है।

व्यवहारिक ज्ञान को महत्त्व

पहला पीसा सर्वेक्षण सन 2000 में आयोजित किया गया था जिसमें 43 देशों के विद्यार्थी बैठे थे। अपने जीवन के 16 वें वर्ष में ही कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठ सकता है। एक विषय का पीसा परीक्षण दो घन्टे का होता है। तीन विषय पढ़ना, गणित व विज्ञान साक्षरता की ही परीक्षा ली जाती है। पीसा में बच्चे की सहज समझ को परखने के साथ मिलजुल कर समाज की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता जाँची जाती है। पीसा में सैद्धान्तिक ज्ञान की बजाय व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक जोर होता है। यह देखा जाता है कि 10 वर्षीय अनिवार्य शिक्षा पूर्ण करने के साथ बच्चा ज्ञानी समाज में नेतृत्व द्वारा लिए जा रहे नीतिगत निर्णयों को समझ सकता है या नहीं। एक जागरूक नागरिक के रूप में सही भूमिका निभा सकने की योग्यता रखता है या नहीं।

पीसा में भारत

भारत ने 2009 के पीसा परीक्षण में तमिलनाडु व हिमाचल प्रदेश के बच्चों को बैठाया था। 400 विद्यालयों के लगभग 16000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। परिणाम अपेक्षा की तुलना में बहुत ही निराशाजनक रहे। 73 देशों के उस मुकाबले में भारत का नम्बर 72 वां स्थान रहा।

मात्र किर्गीस्तान ही भारत से पीछे था। गणित व विज्ञान में औसत 556 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहे शंघाई (चीन) के मुकाबले भारतीय राज्यों ने मात्र 337 व 325 अंक प्राप्त किए थे। परिणाम यह हुआ कि 2012 व 2015 के पीसा सर्वेक्षण में भारत ने अपने बच्चों को नहीं बैठाया। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के कक्षा आठ के विद्यार्थियों का गणित का स्तर दक्षिणी कोरिया के कक्षा 3 के बराबर तथा पढ़ने का स्तर शंघाई के कक्षा 2 विद्यार्थियों के बराबर रहा था।

खिसयानी बिल्ली खंभा नोंचे

2009 में भारत के बच्चे पीसा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके इसका कारण जानने के लिए कोई अनुसंधान नहीं कर हमारे प्रशासकों ने पीसा परीक्षा को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया था। तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई दोष नहीं पीसा के प्रश्न ही भारतीय जनजीवन के अनुकूल नहीं थे। शिक्षा अधिकारियों ने भी एटीएम व एअर बेग आदि पर पूछे गए प्रश्नों को अव्यवहारिक बताया था। पीसा आयोजकों के सामने आपत्ति प्रस्तुत करने की बातें भी कही गई थी। यह आलोचना खिसयानी बिल्ली द्वारा खंभा नोंचने जैसी ही कही जाएगी। लगता है परीक्षा में बैठने से पूर्व पीसा द्वारा प्रसारित विवरणिका को ध्यान से नहीं पढ़ा गया था। अमेरिका सहित अन्य कई देश अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए मगर भारत जैसी प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दी।

निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि पीसा परिणाम का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि भारत के बच्चे बुद्धिहीन होते हैं। मेरी दृष्टि से इसे भारतीय शिक्षा प्रशासन की चूक का उदाहरण माना जाना जाहिए। भारत की माध्यमिक शिक्षा की जिन कमियों की ओर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 7 दशक पूर्व ध्यान आकर्षित किया था उसे हम अभी तक दूर नहीं कर सके हैं। माध्यमिक आयोग ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा जीवन से कटी है। बिना अनुसंधान के परम्परागत रूप से पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण करने में असफल रही है। केवल कुछ विषयों को रटाने को शिक्षा का पर्याय मान लिया गया है। विदेशी भाषा ज्ञान के निर्माण में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। शिक्षण विधियाँ बच्चों में स्वतन्त्र चिन्तन व पहल करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाती। प्रशासनिक बाधाओं के कारण बच्चे व शिक्षक में आत्मिक संबंध नहीं बन पाते। विद्यार्थी के चरित्र निर्माण के बजाय शिक्षक का पूरा ध्यान परीक्षा उत्तीर्ण कराने पर रहता है। परीक्षा को अधिक महत्त्व देने से शिक्षा में जीवन्तता समाप्त होकर यान्त्रिकता हावी हो गई है। आज 70 वर्ष बाद मूल्यांकन करें तो माध्यमिक शिक्षा के दोष बढ़े ही हैं कम नहीं हुए। ऐसे में बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग की बातों पर ध्यान दिया गया होता तो शायद भारत की पीसा 2009 में यह दुर्दशा नहीं होती।

सरकार का पलायन अनुचित

श्री प्रकाश जावड़ेकर के मानव संसाधन मंत्री बनने के बाद भारत सरकार ने देश के बच्चों को पीसा 2018 बैठाने का मन बना लिया था मगर औपचारिकता पूरी करने का समय निकल जाने के कारण अनुमति नहीं मिल पाई है। भारत 2021 में पीसा परीक्षण में सम्मिलित होगा। प्रथमतः इसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन व नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। इसके लिए एक बड़ा निर्णय यह लिया गया है कि इन विद्यालयों में परीक्षा पीसा की तर्ज पर कराई जाएगी ताकि बच्चों को उसका अभ्यास हो सके।

वर्तमान सरकार कुछ प्रयास कर रही है यह अच्छी बात है मगर ये प्रयास पर्याप्त नहीं है। व्यापक व निरन्तर मूल्यांकन को छोड़ कर परीक्षा प्रणाली को पुख्ता करने के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्णय से लगता है कि सरकार दो विपरीत ध्रुवों को एक साथ छूने का प्रयास कर रही है। शिक्षा को पाठ्यपुस्तकों के जंजाल से मुक्त कर बच्चों को विविध माध्यमों से सीखने का वातावरण बनाने कि बजाय हम रटने की प्रवृति को मजबूत करने की ओर बढ़ रहे हैं। आवश्यकता व्यापक व निरन्तर मूल्यांकन की कमियों को दूर करने की चुनौती स्वीकार करने की थी मगर सरकार ने पलायन करना उचित समझा है। इससे नहीं लगता कि 2021 की पीसा में भारत कुछ खास कर पाएगा। सफलता प्राप्त करनी है तो बड़े रणनीतिक निर्णय करने होंगे। ❑

(विज्ञान विषयक लेखक)

किसी भी देश के बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन उनके शिक्षकों के समग्र विकास में योगदान के आधार पर व उनके बौद्धिक ज्ञान के सम्प्रेषण के आधार पर होता है। बार-बार यह प्रश्न उठता है कि वैश्विक-शैक्षिक परिदृश्य में हम कहाँ पर अपने आपको पाते हैं? विभिन्न विश्वस्तरीय मूल्यांकनों के द्वारा विश्व के ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा स्थापित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता रहा है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम वैश्विक परिदृश्य में किससे तुलना करें? यह सही है कि भारत प्राचीन काल में वैश्विक शिक्षा का केन्द्र रहा है। ज्ञान का पहला दीप भी इसी धरा पर ज्योतिर्मान हुआ। परंतु क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के आधार पर हम हमारा मूल्यांकन कर अर्जित स्थान पर चिंता व्यक्त करें या आयातित मूल्यांकन पद्धति के गुण-दोषों पर चर्चा करें।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा

❑ **प्रो. मधुर मोहन रंगा**

संयुक्त-राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मानव सूचकांक-2016 के अनुसार भारत में लोगों के जीवन-स्तर में पिछले सालों की तुलना में उत्साहजनक परिवर्तन आया है। यद्यपि यह बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती है, परन्तु सकारात्मक परिवर्तन की ओर एक इशारा है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त-राष्ट्र किसी भी देश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ज्ञान, लैंगिक-विषमता, आय और जीवन स्तर के संकेतकों को कसौटी मानकर मानव विकास से जुड़ी प्रगति का आँकलन करता है। ग्लोबल स्तर पर हम मानव विकास के मुद्दों पर थोड़ा बेहतर तो हुए हैं। वैश्विक स्तर पर पिछली शताब्दी से शैक्षिक-क्रांति के कारण शैक्षिक प्रतिमानों में परिवर्तन आया है। इसका मुख्य कारण आर्थिक व ज्ञान आधारित समाज रचना है। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा उद्यम व व्यवसाय आधारित हो गया है। भारतीय शिक्षा-तंत्र विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है। (The Indian Economy Review 3.1.11) भारत विश्व का सबसे युवा देश है व यहाँ 140 मिलियन युवाओं का उच्च-शिक्षा प्राप्त करने वाला विशाल समूह है। वर्ष 2030 तक विश्व के प्रत्येक चार स्नातक में से एक भारतीय शिक्षा ग्रहण करने वाला स्नातक होगा क्योंकि भारत का वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य बदल रहा है। भारत में कम लागत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न नवाचार किये गये हैं। विद्यार्थी केन्द्रित-अधिगम-आधारित शिक्षा प्रारूप पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के सकल नामांकन दर में भी वृद्धि हो रही है। शोध की दृष्टि से भारत विश्व के पाँच प्रमुख देशों की श्रेणी में आता है क्योंकि यहाँ के शोधों को सन्दर्भ (citation) के रूप में देखा जाता है। शोध व नवाचार पर 140 बिलियन डॉलर का बजट प्रावधान रखा गया है। भारत के 100 विश्वविद्यालय वैश्विक स्तर पर शोध स्पर्द्धा में खरे उतर रहे हैं। भारत विश्व में ''शोध उत्कृष्टता संरचना'' के चतुर्थ चक्र में है।

पिछले 20 वर्षों में 6 भारतीय प्रतिभाओं ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। भारत वर्तमान में क्षेत्रीय केन्द्र (Regional hub) के रूप में विकसित हो रहा है, यहाँ विश्व के विभिन्न स्थानों से विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने आ रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 21 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

भारत सरकार व यूनेस्को (UNESCO) के सहयोग द्वारा वर्ष 2014 में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2012 में एक लाख, 40 हजार विदेशी विद्यार्थी भारत में अध्ययन हेतु आये; जबकि वर्ष 2014 में यह आँकड़ा बढ़कर 2 लाख, 50 हजार हो गया। भारत में प्राथमिकता के आधार पर निम्न पाठ्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं; जैसे- बी.टेक, बी.काम, बी.ए., एम.बी.बी.एस., बी.फार्म व बी.एससी। एम.बी.बी.एस में 39 देशों के विद्यार्थी बी.टेक में 83, बी.कॉम. में 75 देशों के विद्यार्थी भारत में पंजीकृत हैं। चिकित्सा में सबसे ज्यादा विद्यार्थी कर्नाटक में प्रवेश लेते हैं, जिसमें 79 प्रतिशत विद्यार्थी मलेशिया के होते हैं। बी.टेक में आंध्रप्रदेश में नेपाल से 46 प्रतिशत विद्यार्थी, बी. कॉम. में महाराष्ट्र में बहरीन से 18 प्रतिशत विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। सार्क देशों में अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान व भूटान से विदेशी विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। वर्ष 2011-12 में एम. बी.बी.एस. करने आये, जिनमें 52 प्रतिशत मलेशिया, 24 प्रतिशत अमेरिका, 6 प्रतिशत कनाडा के थे। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 में कुल 2874 विदेशी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आये। बी. टेक. में नेपाल से 40 प्रतिशत भूटान से 12 प्रतिशत, अफगानिस्तान से 11 प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। कुल 2582 विद्यार्थियों ने इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया।

उपरोक्त आँकड़ा का आधार उच्चशिक्षा के अखिल भारतीय सर्वेक्षण को आधार माना गया है। (AISHE,2014) उपरोक्त परिदृश्य भारत में उच्च शिक्षा के स्तर को तो इंगित करता ही है, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा प्रदाता की साख को भी परिभाषित करता है क्योंकि प्रतिवर्ष करीब 21 प्रतिशत विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अत: वैश्विक उच्च शिक्षा के मापदण्ड कुछ भी हैं, उसके स्तर पर हमारे मान्य पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता को इंगित करता है। मैसिव ऑपन ऑन लाइन कोर्सेस (Massive open online courses) में विश्व के 60 प्रतिशत विद्यार्थी जनसंख्या यहाँ पंजीकृत हैं। (www.ey.com) ऑनलाइन एजुकेशन में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में एजुकेशन-टेक प्लेटफार्म तेजी से बढ़ा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पढ़ाई के तरीके को आसान बनाने के लिए 32 एजुकेशन चेनल लाँच किए हैं। ये सभी चेनल डायरेक्ट-टू-होम डिश टी.वी. पर उपलब्ध है। परिवर्तित होते वैश्विक परिदृश्य में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में स्थान प्राप्त करने हेतु हमारे द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर भी मूल्यांकन होना चाहिये। इसी क्रम में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन कराया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के टॉप-100 एजुकेशनल-इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी की है।

ओवर ऑल टॉप-10 में आई.आई.एस.सी. बेगलुरू, आई.आई.टी. मद्रास, बाम्बे, खड़गपुर, दिल्ली, जेएनयू दिल्ली, आई.आईटी. कानपुर, आई.आई.टी. गुवाहाटी, आई.आई.टी. रुड़की व बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय शामिल है, जबकि विश्वविद्यालय में टॉप-10 है, आई आईएससी बेंगलुरू, जेएनयू दिल्ली, बीएचयू वाराणसी, जेएनयू सेंटर फॉर रिसर्च जादवपुर यूनिवर्सिटी, अन्ना युनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अमृता विद्यापीठम् व सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी। रैकिंग के मापदण्ड थे- शोध, पेंटटे, कैम्पस प्लेसमेंट, जॉब, आदि। विश्व के टॉप संस्थान में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 7 है जबकि हमारे आई.आई.टी. संस्थाओं में औसतन 15 हैं। वैश्विक रैंकिंग में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को एक मानक के तौर पर देखा जाता है। हमारे यहाँ लगभग सभी आई.आई.टी. संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में टीचिंग पोस्ट खाली है। विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात के वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी जबकि देश के विश्वविद्यालयों में करीब 4000 हजार शिक्षकों के पद रिक्त है। उल्लेखनीय है कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरू (आई.आई.एस.सी.) का प्रथम स्थान आना स्वाभाविक ही है। क्योंकि यहाँ लम्बे समय से शोध व नवाचार में यह संख्या कार्यरत है। भारत के दो शिक्षण संस्थाओं को पहले 200 विश्वविद्यालयों में स्थान मिला था। यह हमारे संस्थाओं को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होने का संकेत तो है ही।

आज सम्पूर्ण वैश्विक जगत में प्रगति का आधार भौतिक प्रतिमानों को माना जा रहा है। विज्ञान, वैज्ञानिक-अनुसंधानों व आर्थिक मापदण्डों को यदि भौतिक प्रगति का आधार माने तो यह परिभाषा उचित लगती है। परंतु आज परिवर्तित होते विकास के मापदण्डों में आधुनिक प्रगति को ही विकास का आधार मान लिया गया है। वैसे राष्ट्र की उन्नति भौतिक प्रतिमानों के साथ-साथ आध्यात्मिक आधारों पर भी अवलम्बित रहती है। जिसमें शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश के बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन उनके शिक्षकों के समग्र विकास में योगदान के आधार पर व उनके बौद्धिक ज्ञान के सम्प्रेषण के आधार पर होता है। बार-बार यह प्रश्न उठता है कि वैश्विक-शैक्षिक परिदृश्य में हम कहाँ पर अपने आपको पाते हैं? विभिन्न विश्वस्तरीय मूल्यांकनों के द्वारा विश्व के ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा स्थापित मूल्यांकन पद्धति के द्वारा किया जाता रहा है। अत: यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम वैश्विक परिदृश्य में किससे तुलना करें? यह सही है कि भारत प्राचीन काल में वैश्विक शिक्षा का केन्द्र रहा है। ज्ञान का पहला दीप भी इसी धरा पर ज्योतिर्मान हुआ। परंतु क्या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के आधार

पर हम हमारा मूल्यांकन कर अर्जित स्थान पर चिंता व्यक्त करें या आयातित मूल्यांकन पद्धति के गुण-दोषों पर चर्चा करें।

आज का यह विषय उभर कर आता है कि हमारे विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय मापदण्डों के रैंकिंग के प्रथम 200 में भी नहीं आते हैं। हर मंच से यही प्रश्न उठाया जाता है। कुल मिलाकर दोष शिक्षकों के ऊपर ही आता है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि हमें उन मापदण्डों पर विचार करना होगा। जिनके आधार पर विश्व-स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग की जाती है। वर्तमान समय में अमेरिका व ब्रिटेन की 4-5 रैंकिंग एजेंसिया कार्यरत हैं, क्वाक्वा डेली सिमोन्डस दुनिया की विश्वविद्यालय रैंकिंग (Quackwa Delli Symonds world University Ranking, QS,WUR), टाइम्स-उच्चशिक्षा दुनिया की विश्वविद्यालय रैंकिंग (Time's Higher Education world University Ranking, THEWUR), संयुक्त राज्य अमेरिका-नवीन दुनिया विश्वविद्यालय रैंकिंग (United States New World University ranking USNWUR) व थामस रियूटर्स रेपुटेशन सर्वेक्षण (Thomas Reuter's Global Reputation Survey, TRGRS) है। दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग-2003 में चीन की शंघाई जियाटोंग विश्वविद्यालय (Shanghai Jaitong University, the People's Republic at China) ने प्रारंभ किया था। अन्तर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए निर्धारित मानदण्डों पर हमारे विश्वविद्यालय खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि वित्त या निवेश की कमी, वृहद कक्षाएँ, विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात अधिक, विश्वस्तरीय शोध व नवाचारों की कमी, आधुनिक अधिगम व शिक्षण प्रणाली का अभाव, अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रति अरुचि; इनके अतिरिक्त प्रत्येक संकाय सदस्यों के शोध का प्रभाव जिसे सन्दर्भ सूचक (Citation index) के रूप में मान्यता प्राप्त है, कम होना। उपरोक्त कमी के कारण हमारे विश्वविद्यालयों की अन्तरराष्ट्रीय रैंकिंग में स्थिति कमजोर है। परन्तु यहाँ पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या हमें विश्व स्तरीय निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अपना मूल्यांकन कराना होगा या हमारे भारतीय मापदण्डों के आधार पर। हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (National Assessment and Accreditaion Council)-नैक कार्यरत है। इनके कुछ मापदण्ड हमारे परिप्रेक्ष्य में सही है व कुछ अन्तरराष्ट्रीय मापदण्डों के अनुसार है। अत: आवश्यकता इस बात की है कि परिस्थिति-सापेक्ष मापदण्ड बनाकर मूल्यांकन की आवश्यकता है। आवश्यकता इस बात की भी है कि वित्त पोषण समान हो। यह विशेष उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक वित्त प्राप्त होता है जबकि सकल नामांकन दर (GER) राज्य विश्वविद्यालय अधिक हैं। शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार करना होगा। शोध व नवाचारों को बढ़ाने हेतु आधार-भूत संरचना में परिवर्तन, अधिगम व शिक्षण प्रणाली को आधुनिक बनाने, शोध को प्रयोगशाला से वास्तविक प्रयोग स्थल पर ले जाने, शिक्षकों की सम्पूर्ण सुविधाओं को दृष्टिगोचर कर समुचित परिवर्तन करने से ही शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर सकेंगे। इन्डियन एक्सप्रेस में 11 मई, 2014 में छपे एक लेख के आधार पर-निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन कई माह तक नहीं मिलता है। इसी प्रकार टाइम्स ऑफ-इन्डिया दिनाँक-16 फरवरी, 2016 के अनुसार-उच्च शिक्षण संस्थाओं में मुख्य रूप से महाविद्यालयों में 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षक तदर्थ रूप में कार्यरत हैं। उच्चशिक्षा विभाग में रिक्त पदों की जानकारी के सही आँकड़े उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। संसदीय स्टैंडिंग समिति (Parliamentary Standing Commitee) की मई, 2015 की रिपोर्ट के आधार पर-कुछ आँकड़े इस प्रकार हैं- कुल स्वीकृत शिक्षकों के पद 16,324 हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में उनमें से 38 प्रतिशत रिक्त हैं। इसी प्रकार राज्य विश्वविद्यालयों में करीब 40 प्रतिशत पद रिक्त है। अस्थाई, संविदा, पूर्णत: अस्थाई, अतिथि शिक्षक को करीब 4,000 से 20,000 प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। उपर्युक्त सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन के मापदण्डों के आधार पर देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य के विश्वविद्यालयों, स्वायत्त महाविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों में सम्पूर्ण आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के साथ आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शोध व नवाचार को भारतीय सापेक्ष में ढालना होगा। तभी विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में हमें स्थान मिल सकेगा, साथ ही हमारे द्वारा विकसित की गई मूल्यांकन पद्धति के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना होगा व शिक्षा मूल्यांकन, भारतीय प्रतिमानों के आधार पर करना होगा।

भारतीय त्रिस्तरीय शिक्षा-व्यवस्था, जैसे-लक्ष्य आधारित शिक्षा विस्तार, विद्यार्थी केन्द्रित, अधिगम आधारित व गुणवत्तापूर्ण तकनीकी आधारित शिक्षा के कारण विद्यार्थियों की क्षैतिज व उर्ध्व (horizantal and vertical) गति बढ़ेगी व विद्यार्थियों में प्रतिभा के साथ-साथ सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व आध्यात्मिक भारतीय चिंतन की ओर अग्रसर होकर वैश्विक प्रतिमानों को प्राप्त कर सबल व सक्षम राष्ट्र निर्माण के भागीदार होंगे व वैश्विक परिदृश्य में भारतीय प्रतिभा की श्रेष्ठता अधिक प्रभावी प्रकार से स्थापित कर सकेंगे। ❑

(विभागाध्यक्ष, पर्यावरण विज्ञान विभाग, सरगुजा वि.वि., अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़)

मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन द्वारा सीखने व क्षमता अनुसार विकसित करके व जाँचने के विकल्प रखे जाए। प्राथमिक स्तर पर बोर्ड परीक्षाएँ सुधार के स्थान पर तनाव बढ़ाती है। पाठ्यपुस्तकें आधुनिक गैजेट्स के होते हुए भी पाठ्यपुस्तकें शिक्षण का सशक्त माध्यम है, इनमें परिवर्तन द्वारा विद्यार्थी के विचार की दिशा को बदला जा सकता है। पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों, व सम्पूर्ण सृष्टि के लिये पर्यावरण संरक्षण तथा देश की सुरक्षा जैसे विषयों द्वारा वे राष्ट्रीय तथा वैश्विक समस्याओं से जुड़ेंगे, विकास के लिये सहयोग देंगे तथा जागरूक नागरिक बनेंगे। शिक्षकों द्वारा सौहार्दपूर्ण व प्रेरक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में हो तथा स्थानीय वक्ताओं व शिक्षाविदों के विचारों से विद्यार्थी अवगत होंगे तो स्थानीय भाषा व संस्कृति से भी जुड़ेंगे।

विश्वस्तरीय शैक्षिक प्रबन्धन आवश्यक

❑ **डॉ. रेखा भट्ट**

ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों से सिद्ध है कि ईसापूर्व पाँचवी तथा छठी शताब्दी में भारतवर्ष में नालन्दा व तक्षशिला जैसे विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान थे। यहाँ विदेशों से शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इन विश्वविद्यालयों में साहित्य, व्याकरण, धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष, प्रबन्धन, आयुर्वेद जैसे विषयों के साथ ही मानव व पशु चिकित्सा, शिल्पकारी, तकनीकी एवं व्यवसायिक सभी प्रकार की उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। अनेक देशों के विद्यार्थियों को व्यापार सम्बन्धी, अध्यापन कला, युद्ध कौशल, प्रशिक्षण एवं सैन्य संचालन का भी ज्ञान दिया जाता था। 'मनुस्मृति' एवं 'अर्थशास्त्र' जैसे उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथ थे जो आज भी प्रासंगिक है। शिक्षण के लिये विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। समाज द्वारा दिये जाने वाले दान से ही शिक्षा पर होने वाला व्यय वहन किया जाता था। शिक्षा को जनसामान्य के लिये सुगम बनाने के उद्देश्य से स्तूपों, मन्दिरों व मठों में शिक्षा दी जाने लगी। इनमें समाज के श्रेष्ठ, प्रतिष्ठित, विद्वत् शिक्षक विश्व में भारतीय ज्ञान-विज्ञान की स्थिति को उच्चतर बनाने की दृष्टि से शिक्षा प्रदान करते थे।

भारत में विदेशी आक्रमणों एवं पराधीनता के कारण कई शताब्दियों तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई। भारत को गुलाम बनाये रखने की दृष्टि से ब्रिटिश शासन ने भारतीय मूल शिक्षण पद्धति को नष्ट कर दिया केवल कुलीन वर्ग के लिये तथा प्रशासकीय कार्यों में सेवकों व लिपिकों की भर्ती के लिये शिक्षा को सीमित कर दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जड़वत औपनिवेशिक शिक्षण प्रणाली में सुधार के प्रयास किये गये। महात्मा गाँधी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय आदि ने ऐसे शिक्षण संस्थान स्थापित किये जिनका अनुसरण किया जा सके और मैकालयी शिक्षा पद्धति को समाप्त किया जा सके, किन्तु ये संस्थान स्वयं एक उदाहरण बने रह गये। शिक्षा के वैश्विकरण तथा तेजी से बढ़ते तकनीकी एवं नवाचार के अनुरूप नीतियों के अभाव में गत 70 वर्षों में गठित अनेक आयोग व समितियाँ शैक्षिक प्रबन्धन में सफल नहीं हो सकीं हैं।

स्वतंत्रता से पूर्व भारत में साक्षरता 98 प्रतिशत थी, क्योंकि प्रत्येक गाँव-कस्बे में गुरुकुल व पाठशालाएँ थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साक्षरता मात्र 18 प्रतिशत रह गई। धीरे-धीरे विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या बढ़ने से प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ा, महिला शिक्षा में भी वृद्धि हुई किन्तु विश्व श्रेणीकरण में भारत का

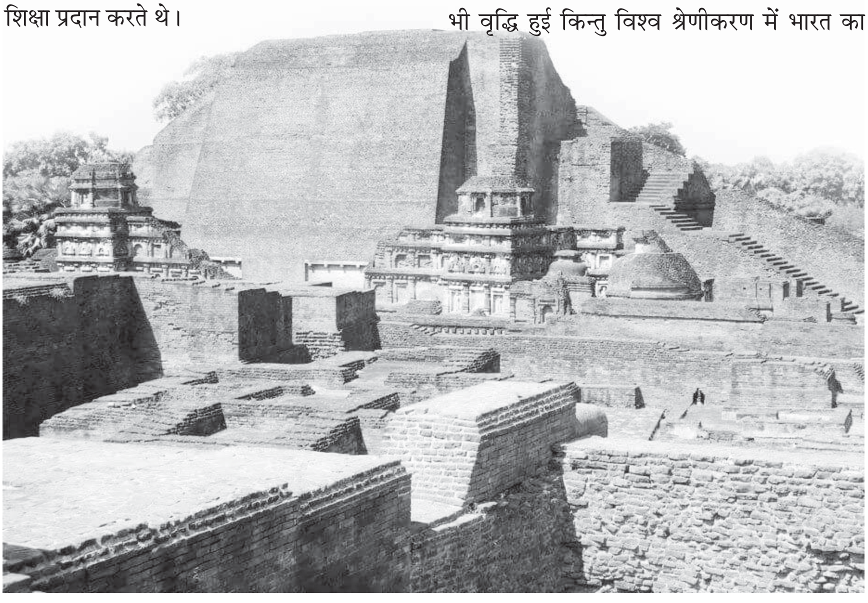

स्थान बहुत पीछे है। जापान और पश्चिमी यूरोप के छोटे-छोटे देशों, डेनमार्क, स्वीडन आदि में पिछले कई वर्षों से साक्षरता सौ प्रतिशत है। आज ये सभी देश आर्थिक रूप से विकसित व मजबूत देश हैं। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च स्तरीय कहे जाने वाले भारत के अन्य शैक्षिक संस्थान वैश्विक स्तर पर शिक्षा के न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं करते। भारत में ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक विस्तृत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज आधारभूत शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो सकी। विश्व के अन्य देशों में तकनीकी विकास द्वारा व्यापक रूप से सर्वसुलभ, शिक्षा उपलब्ध है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षा कक्ष एवं मूलभूत ढाँचा जैसे पुस्तकालय, खेल का मैदान तथा शैक्षणिक सामग्री जैसी प्राथमिक आवश्यकताएँ भी पूर्ण नही हो पाती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिये 38957 करोड़ रुपये 2011-12 में आवंटित किये गये थे, इसमें दोपहर भोजन (मिड-डे मील) व शिक्षा पर खर्च को जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के प्रावधान आज तक पूरे नही हो सके। केन्द्र व राज्य सरकार के अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा भी वर्ष 2000 में 2 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। इसमें अतिरिक्त 400 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को एक्सीलेंस सेन्टर बनाने के उद्देश्य कई वर्षों में पूर्ण नही हो सके हैं।

भारत की उच्च शिक्षा विश्व का सबसे बड़ा शिक्षण तंत्र है, जिसमें दस करोड़ से अधिक विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उच्च शिक्षा में सुधार के तहत प्रत्येक वर्ष नियमित महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती है किन्तु संसाधनों एवं शिक्षकों की उपलब्धता में अनुपातिक वृद्धि नहीं होती। इन संस्थानों में प्रतिवर्ष बढ़ाई गई सीटों को भरने के लिये प्रवेश की पात्रता व योग्यता के मानक अत्यन्त सरल व लचीले कर दिये जाते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में भी विद्यार्थी की योग्यता व क्षमता मापने के सीसीई व सीबीएसई जैसी विदेशों से ली गई मूल्यांकन पद्धतियों को भारतीय परिवेश में लागू करने के प्रयास सफल नहीं हो सके है। पाठ्यक्रमों में आधुनिक समय के अनुसार सुधार एवं परिवर्तन अपेक्षित है। विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों पर एक ही तरह के उपस्थिति नियम लागू नहीं किये जा सकते। विश्व में केवल भारत में उच्च शिक्षा में पिछड़ी जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित सीटों के कारण अनेक प्रतिभाशाली विद्यार्थी वंचित हो जाते हैं तथा स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी मँहगे निजी संस्थानों में प्रवेश लेने को मजबूर होते हैं। आर्थिक लाभ के लिये खोले गये निजी संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता के लिये जवाबदेह नहीं है।

शिक्षा व्यक्ति को स्वयं का जीवन उन्नत करने के साथ समाजोत्थान में जीवनपर्यन्त योगदान देने में सक्षम बनाती है। इसके लिये अन्य देशों में विद्यार्थी को शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारित कर सीखने, समझने व नया करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं। उनमें रचनात्मकता, समस्याएँ सुलझाने की क्षमता, नवीन परिकल्पनाएँ, शोध का अनुभव व सृजनात्मकता विकसित हों, ऐसे पाठयक्रमों का निर्धारण किया जाता है। भारत में मूल शैक्षणिक काल में विद्यार्थी IIT, JEE, AIM व CLAT आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निर्धारित प्रश्नों के अभ्यास के लिये कोचिंग कक्षाओं में व्यस्त रहते हैं। यही कारण है कि गत वर्षों में भारत ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, पेप्सी, आई.सी. आई.सी.आई., इन्फोसिस जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये उच्च पैकेज वाले कामगार ही दिये हैं। जबकि अनेक देशों ने विश्व को बड़े उद्योगपति, वैज्ञानिक, शोध व अनुसंधानकर्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ प्रदान किये हैं। विश्व के अन्य देशों में शिक्षा के उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा है। अच्छे ग्रेड प्राप्त करना, साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करना, अतिरिक्त परीक्षाएँ जैसे- यू.के. में VBMAT, STEP, MAT, TSA आदि उत्तीर्ण करने जैसी अनिवार्यता है। सम्पूर्ण शिक्षण काल में विद्यार्थी शिक्षण द्वारा इस योग्य बनता है कि उसके पास कार्य करने के कई विकल्प होते हैं, उस पर किसी प्रकार का मानसिक दबाव नही होता है। मँहगे विदेशी शिक्षण की ओर प्रतिभा पलायन के कारण भारत को मुद्रास्फीति एवं

योग्य प्रतिभाओं का नुकसान होता है। कई भारतीय अभिभावक भारी कर्ज लेकर भी विदेशी शिक्षण का खर्च वहन करते हैं।

भारत की 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी में बच्चों को कृषि कार्यों में तथा शेष गरीब वर्ग में पारिवारिक आय में योगदान के लिये कार्य करने को प्रेरित किया जाता है। भारत में प्राथमिक स्तर के बाद विद्यालय में उपस्थिति एवं नामांकन में कमी का यह महत्त्वपूर्ण कारण है।

अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत तभी टिकेगा, जब भारत के अधिकाँश ग्रामीण व गरीब जनसंख्या को कौशल, व्यवसायिक, औद्योगिक व तकनीकी शिक्षा द्वारा सशक्त किया जाये। शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि के साथ उन पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये शिक्षा प्रबंधन को विस्तृत करने व कार्यप्रणाली के नियमों में सुधार की आवश्यकता है। विश्व स्तरीय मानकों को पूरा न कर सकने वाले संस्थानों का प्रत्यायन (Accredition) समाप्त कर बढ़ी हुई संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे सभी शिक्षण संस्थानों को संसाधन व शिक्षक उपलब्ध करवाये जा सकेंगे। विद्यालयों में मिड डे मील जैसी योजनाएँ शिक्षण कार्य को बाधित करती है तथा शिक्षा का स्तर गिरता है। श्रेष्ठ शिक्षण एवं परिणामों से शिक्षा सेवा के प्रति समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ निवेशकों को शिक्षा क्षेत्र में उदारतापूर्वक निवेश के लिये प्रोत्साहन मिलेगा तो शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीक भी उपलब्ध हो सकेगी। इससे शिक्षा दूरस्थ एवं एकाकी क्षेत्रों में भी पहुँचेगी। विश्वस्तरीय नवीन तकनीकी निर्माण व उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक शोध व अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए शिक्षा का औद्योगिक व व्यावसायिक समन्वय तथा निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। शोध व शोध पत्रों की अनुशंसा हेतु उचित प्रणाली के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन से उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर पहचान प्राप्त होगी।

मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन द्वारा सीखने व क्षमता अनुसार विकसित करके व जाँचने के विकल्प रखे जाए। प्राथमिक स्तर पर बोर्ड परीक्षाएँ सुधार के स्थान पर तनाव बढ़ाती है। पाठ्यपुस्तकें आधुनिक गैजेट्स के होते हुए भी पाठ्यपुस्तकें शिक्षण का सशक्त माध्यम है, इनमें परिवर्तन द्वारा विद्यार्थी के विचार की दिशा को बदला जा सकता है। पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों, व सम्पूर्ण सृष्टि के लिये पर्यावरण संरक्षण तथा देश की सुरक्षा जैसे विषयों द्वारा वे राष्ट्रीय तथा वैश्विक समस्याओं से जुड़ेंगे, विकास के लिये सहयोग देंगे तथा जागरूक नागरिक बनेंगे। शिक्षकों द्वारा सौहार्दपूर्ण व प्रेरक वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में हो तथा स्थानीय वक्ताओं व शिक्षाविदों के विचारों से विद्यार्थी अवगत होंगे तो स्थानीय भाषा व संस्कृति से भी जुड़ेंगे। कम आय वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर से ही कला कौशल व्यवसाय उद्यमों में दक्षता के लिये प्रशिक्षण देने से वे जीविकोपार्जन में सक्षम होंगे तभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये आगे बढ़ेंगे।

भारत में सामाजिक व भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियों के साथ शिक्षा के प्रारूप में भी अन्तर होगा, तभी शिक्षा सर्वसामान्य के लिए ग्रहण करने योग्य होगी। सम्पूर्ण शिक्षा तंत्र का समाज व वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप प्रबन्धन आवश्यक हो गया है। भारतीय परिवेश के अनुरूप शिक्षा का पुनरुत्थान विद्यार्थी को समाज में योगदान देने की क्षमता प्रदान करेगा तथा देश का आर्थिक विकास संभव होगा। ऐसा होने पर भारत में पुनः ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित होगी और विश्व में भारतीय शिक्षा की उत्कृष्ट पहचान बनेगी। ❑

(व्याख्याता-रसायन शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर)

वर्तमान परिदृश्य और शैक्षिक उपलब्धि

यदि हम वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों पर और बदलते विश्व परिदृश्य में बच्चों को खरा उतारना चाहते हैं, तो हमें आन्तरिक व्यवस्थाओं व शिक्षा पर अत्यधिक राजनैतिक दखलंदाजी से होने वाले दुष्प्रभावों का व्यापक मंथन कर उनमें अपेक्षित सुधार लाने के सुनिश्चित व समयानुकूल प्रयास करने होंगे। शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ लोगों के रोजगार-स्तर को बढ़ाने हेतु 'महानरेगा' जैसी योजनाएँ शिक्षित हो रहे बच्चों के लिए भी लाई जानी चाहिए, ताकि शिक्षा प्राप्ति पश्चात उन्हें दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। उनमें व्यवसायपरक कौशलों का विकास हो। सही मायनों में अपनी शिक्षा का उपयोग स्वयं के, समाज के और राष्ट्र के विकास में कर सकें। ताकि वे अपने भविष्य को लेकर संशय, उदासीनता और नैराश्य में न रहें।

❑ **डॉ. इन्दु बाला अग्रवाल**

'हम भारत के भरत खेलते शेरों की सन्तान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिन्दुस्तान से' ये पंक्तियाँ मात्र गर्वोक्ति नहीं है। भारतवर्ष संसार के मानचित्र में अपना स्थान बनाये हुए है। धन, धान्य सम्पदा से सम्पन्न राष्ट्र है। प्रकृति मेहरबान है। हर प्रकार के खनिज संसाधन, जल की प्रचुरता, ऊष्ण जलवायु उचित तापमान, श्रम शक्ति की उपलब्धता आदि सभी भरपूर मात्रा में मददगार हैं। इन्हीं कारणों से प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और आज तक भारत की तरफ विदेशी लोग लालायित दृष्टि से देखते हैं। विश्व क्षेत्रफल का मात्र 2.42 प्रतिशत भू-भाग हमारे पास उपलब्ध है जबकि विश्व जनसंख्या की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है और मानव संसाधन उपलब्ध करवाती है। 2011 की जनसंख्या के आँकड़ों के हिसाब से 121.0854 करोड़ लोग भारत में निवास करते हैं।

भारत जिसका गौरव गान सदियों से विश्व गा रहा है जिसने अध्यात्म और ज्ञान में विश्वगुरु होने का दर्जा हासिल कर अपना परचम फैलाया था। चरक, आर्यभट्ट, नागार्जुन जैसे महान विद्वान् यहाँ पैदा हुए हैं। तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालय विश्व को भारत की देन है। अनेक ज्ञान पिपासु चीनी यात्री जिनमें फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, मार्को पोलो भारत में विद्याधन अर्जन के लिए आये। विश्व को शून्य (जीरो) की संकल्पना भारत की देन है। स्थापत्य कला, संगीत, साहित्य, ज्योतिष विज्ञान जैसे हर क्षेत्र में विश्वजन भारत का लोहा मानते आए हैं। लेकिन ये उपलब्धियाँ मात्र प्राचीन काल की देन नहीं हैं। आज भी भारत विश्व के चुनिंदा राष्ट्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। आज भारत परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र है जिसका उपयोग वह विध्वंसक रूप में ना कर शांतिपूर्ण कार्यों यथा बिजली उत्पादन हेतु कर रहा है। भारत ने अनेक कृत्रिम उपग्रहों की स्थापना अंतरिक्ष में की है, मंगल ग्रह पर मंगलयान से जीवन की खोज, चन्द्रमा पर वातावरण सृजन आदि। हर गोविन्द खुराना, चन्द्रशेखर, अमर्त्य सेन जैसे महान वैज्ञानिक व अर्थशास्त्री भारतीय मूल के हैं, जिनको नोबल पुरस्कार मिला है। सी. वी. रमन, रामानुजम अनेकों ऐसे नाम हैं, जिन के कार्यों व खोजों द्वारा अनेक अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया गया है। परन्तु भारत का भाग्य बदल सकने की क्षमता और शक्ति रखने वाला मस्तिष्क भारत में उपयुक्त प्रोत्साहनों के अभाव में अपनी सेवाएँ विदेशों को देने को मजबूर है, अर्थात् देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन में अधिकांश उच्च कौशल युक्त व उच्च दिमागी क्षमता रखने वाले मेधावी विदेशों में पलायन कर अपने ज्ञान का उपयोग वहाँ कर रहे हैं और उन देशों की तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आवश्यकता है रिवर्स ब्रेन ड्रेन करने की, ताकि उनकी योग्यताओं और क्षमताओं का फायदा उठाया जा सके। दूसरी तरफ एक अलग तस्वीर है, जो भारतवर्ष की उज्ज्वलता की तस्वीर ना दिखाकर अंधकार की तस्वीर दर्शाती है। कुछ आँकड़े जिन पर गौर करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर वर्ष UNDP (United Nations Development Programme) के तहत विभिन्न राष्ट्रों के मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है जो तीन पहलुओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है। 2015 में 188 देशों में भारत का स्थान 131 आया है जो लगभग पाकिस्तान और अफ्रीकी देश केन्या के समकक्ष है।

एक अध्ययन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा दक्षिणी एशियाई देशों में गरीबी का अनुमान लगाने हेतु किया गया, जिसमें अफगानिस्तान के पश्चात् दक्षिणी एशियाई देशों में भारत को सर्वाधिक गरीब राष्ट्र बतलाया गया व यह भी बतलाया गया कि 49 देशों के कुल गरीबों के 40 प्रतिशत गरीब लोग भारत में रहते हैं, यह निष्कर्ष बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multi - dimensional poverty index) 2014 के अनुसार निकाला गया। हमारे द्वारा करोड़ों रूपये खर्च कर ओलम्पिक खेलों में बड़े-बड़े दल भेजे जाते रहे हैं लेकिन एक भी स्वर्ण पदक भारत की झोली में नहीं आता।

हर क्षेत्र में राजनैतिक दखलंदाजी देखने को मिलती है जिसके कारण से प्रतिभाएँ हताश होती हैं, उभरकर नहीं आ पातीं। ना केवल अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यक्रम (PISA) से भारतीय बच्चों के निम्नस्तरीय ज्ञान का पता लग रहा है वरन् विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के निष्कर्ष निम्नस्तरीय विकास को स्पष्ट कर रहे हैं। अर्थात् विकास के पायदान पर हम इतना नीचे हैं, तो शिक्षा में उपलब्धि हासिल कर सकने जैसी क्षमता हमारे बच्चे कहाँ से जुटा पाएँगे, जबकि विकास व शिक्षा एक दूसरे की पूरक है। देश आजाद हुआ एवं हमने समाजवाद की संकल्पना को अपनाया। जन-जन के विकास व कल्याण को वरीयता देने की बात की गई लेकिन धीरे-धीरे साम्राज्यवादी व पूँजीवादी ताकतें देश पर हावी होती गयी, समस्त योजनाएँ व निर्णय पूँजीवादियों के अनुकूल उन्हें लाभ देने हेतु लिए जाने लगे। सड़कों को चौड़ी करना, सेज, मॉल आदि की स्थापना हेतु कृषकों से उनकी बेशकीमती जमीन हड़प कर ली जाती है। ताकि उन चौड़ी सड़कों पर बड़ी-बड़ी कारें आसानी से दौड़ सकें, विदेशी कार उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। इतनी अधिक जनसंख्या होने के कारण विश्व हमें बढ़ते बाजार की संभावना और उपभोक्ता के रूप में देख रहा है। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अत्यधिक मात्रा में ऋण लेने के कारण सरकारें, विदेशी संस्थाओं की बातें मानने हेतु मजबूर हैं।

अनुकूल मौसम से होने वाले अति उत्पादन के अनुपयुक्त भण्डारण क्षमता व निम्न समर्थन मूल्य से होने वाली किसानों की बर्बादी से सरकारें उन्हें बचाने में अधिक सफल नहीं हो पा रही हैं। कई भारतीय किसान पेटेंटीकृत बीज, खाद और दवाइयों को खरीदकर ऋणग्रस्तता के भयावह जाल में फँस कर आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। विभिन्न शोध अध्ययन यह दर्शाते हैं कि बच्चों की उपलब्धि पर मात्र I.Q. level या कक्षा की पढ़ाई प्रभाव नहीं डालती वरन् घर-परिवार की सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थिति भी प्रभाव डालती है। यदि माता-पिता हताश व बेबस हैं तो उपलब्धियाँ हासिल करना सहज नहीं है।

दूसरी तरफ शिक्षा रोजगार से जुड़ी ना होने के कारण गरीब माता-पिता यह देखते हैं कि 10-15 वर्षों की पढ़ाई के पश्चात् भी बच्चा कमाई योग्य नहीं हुआ है, बल्कि पढ़ाई से उसकी कार्यक्षमता का ह्रास हुआ है। 'कहावत भी है कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला'। उपलब्धि बढ़ाने हेतु आवश्यकता, शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की है। शिक्षा में भविष्य का प्रतिबिम्ब दिखना चाहिए। अनिश्चित व असुरक्षित भविष्य ज्ञान के धारण (Retention) में सबसे बड़ी बाधा है। ऐसा भी नहीं है कि गाँवों व सरकारी स्कूलों में ही बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भव्य इमारतों वाले विद्यालय जो लूट का क्षेत्र बने हुए है उनका पूरा ध्यान रटन्त विद्या (Rote memorisation) पर है जिससे जो रात को पढ़ा, वह दिन को सफा वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। डमी विद्यालयों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग क्लासेज हर गली, मोहल्ले और चौराहों पर खुलती जा रही हैं, जहाँ अप्राकृतिक माहौल में यंत्रवत तरीकों से शिक्षा दी जा रही है जिसमें किसी भी प्रकार के अनुभवों हेतु कोई स्थान नहीं है। अभिभावकों की अपेक्षा है कि बच्चा कुछ सीखे कुछ बन जाए। प्रतिस्पर्धी युग में डॉक्टरी या इन्जीनीयरिंग कॉलेज में बच्चा स्थान बना पाए इस आशा में अपने सब सपनों व आकाँक्षाओं को भुलाकर अभिभावक मनमानी फीस अदा कर विद्यालय से आते ही शाम 4 बजे बस्ता थमा देते हैं। गली, मौहल्लों, चौराहों पर बच्चों के झुण्ड के झुण्ड खेलते नजर आते थे वह दृश्य विलुप्त है, अर्थात् peer group में सीखना, सामाजिकता का विकास, शारीरिक व मानसिक विकास, नेतृत्त्व व अनुशासन का विकास सब कल की बातें हो गयी। एक तरफ बच्चे पर बढ़ते मानसिक बोझ का तर्क देकर कक्षा VIII तक अनुत्तीर्ण न करने व बोर्ड परीक्षा को हटाने जैसे प्रयोग किए गए हैं और दूसरी तरफ बच्चों को यंत्रवत मशीन बनाया जा रहा है। अनेकों विरोधाभासों के चलते हमारी लंगड़ाती शिक्षा व्यवस्था जो आज भी लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति का अनुसरण कर रही है, पाठ्यक्रमों व किताबों में नवीनता लाने हेतु हर सरकार द्वारा नई कमेटियाँ गठित कर दी जाती हैं, परन्तु हर नई कमेटी 'नई बोतल में पुराना पानी' अर्थात् लेवल और रैपर बदलकर वही पुरानी चीजों पर अपना नाम आरोपित कर वाहवाही लूटती नजर आती है और वहीं ठगा का ठगा रह जाता है अभिभावक और विद्यार्थी।

यदि हम वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों पर और बदलते विश्व परिदृश्य में बच्चों को खरा उतारना चाहते हैं, तो हमें आन्तरिक व्यवस्थाओं व शिक्षा पर अत्यधिक राजनैतिक दखलंदाजी से होने वाले दुष्प्रभावों का व्यापक मंथन कर उनमें अपेक्षित सुधार लाने के सुनिश्चित व समयानुकूल प्रयास करने होंगे। शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ लोगों के रोजगार-स्तर को बढ़ाने हेतु 'महानरेगा' जैसी योजनाएँ शिक्षित हो रहे बच्चों के लिए भी लाई जानी चाहिए, ताकि शिक्षा प्राप्ति पश्चात उन्हें दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। उनमें व्यवसायपरक कौशलों का विकास हो। सही मायनों में अपनी शिक्षा का उपयोग स्वयं के, समाज के और राष्ट्र के विकास में कर सकें। ताकि वे अपने भविष्य को लेकर संशय, उदासीनता और नैराश्य में न रहें। अपने को ऊर्जावान व कौशल युक्त बनाकर भविष्य के सपनों को अंजाम देने की क्षमताओं का विकास कर सकें। तब सुनिश्चित भविष्य की छवि यकीनन तौर पर उपलब्धि में वृद्धि दर्ज करवाएगी।❑

(पूर्व तदर्थ व्याख्याता, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर)

माध्यमिक शिक्षा का असली चेहरा

❑ बजरंगी सिंह

केन्द्र और राज्य सरकारों के वर्षों के प्रयास के बाद भी भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हो सका। गौर करें तो पता चलता है कि सब बुनियादी पहल शिक्षकों की योग्यता का है जिसको हमेशा नजरन्दाज किया गया। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं। इस सवाल पर गौर करने से पता चलता है कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया भ्रष्ट और गैर पारदर्शी है। यहाँ बता दें कि आज शिक्षकों का पेशा काफी आकर्षक और आसान बन गया है। क्योंकि यहाँ वे तभी काफी आकर्षक और सेवा सुरक्षा की भी लगभग गारन्टी है। फिर भी अच्छे और योग्य लोग शिक्षण कार्य में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इसका अन्वेषण करने के बाद पता चलता है कि चयन प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पैसे के बल पर दोयम दर्जे के लोग तो चयन में सफल हो जा रहे हैं किन्तु योग्य और प्रतिभावान लोग पीछे छूट जाते हैं।

शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा का अत्यधिक महत्त्व है। क्योंकि यह शिक्षा का मेरुदण्ड है। इसके बाद ही छात्रों के भावी जीवन की शुरुआत होती है और उच्च शिक्षा का दरवाजा भी उनके लिए खुल जाता है। माध्यमिक शिक्षा इतनी महत्त्वपूर्ण होते हुए भी उसे वो प्राथमिकता नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का मेरुदण्ड कमजोर होता गया और उसके ऊपर उच्च शिक्षा का भवन भी हम खड़ा करते गए। स्थिति यह हो गई कि आज न माध्यमिक शिक्षा सुदृढ़ है और न ही उच्च शिक्षा को मजबूती मिल पाई। प्राथमिक शिक्षा का हाल तो वैसे ही बेहाल है। ऐसे में हमें माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियों को समझना होगा और उसके निदान के लिए एक ठोस नीति तैयार करनी होगी।

वर्तमान नीति का उद्देश्य 14 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस समय माध्यमिक शिक्षा अधिकतर निजी हाथों में है। उसके चलते शिक्षा कम और व्यापार अधिक हो रहा है। परिणाम यह हुआ कि शिक्षा और परीक्षा दोनों भगवान भरोसे हो गई। पैसा दो, प्रमाण पत्र ले जाओ। परीक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की जो स्थिति है वह किसी से छिपी नहीं है। परीक्षा पर पूरी तौर पर नकल माफियाओं का कब्जा है। पैसे के हिसाब से श्रेणियाँ बाँटी जा रही है। इसका दृश्य अभी हाल में बोर्ड परीक्षाओं में देखने को मिला है।

माध्यमिक शिक्षा राज्यों में वित्तविहीन है, राजकीय विद्यालयों की संख्या अपेक्षा से बहुत कम है। इस तरह यदि यह कहा जाए कि आज माध्यमिक शिक्षा का निजीकरण होता जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्कूलों के संचालन में नेता, अभिनेता, व्यावसायी और उद्योगपति जैसे तमाम लोगों की अहम भूमिका हो गई है। क्योंकि यह सरल और सम्मान-जनक जरिया बन चुका है। किन्तु शिक्षकों की यहाँ स्थिति बहुत चिन्ताजनक और दुखद है वेतन के नाम पर केवल रस्म अदायगी ही है। यही वजह है कि इन स्कूलों में प्रशिक्षित और पात्र अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। उसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। फिर भी वित्त विहीन मान्यता प्राप्त स्कूलों को हर वर्ष बड़ी संख्या में मान्यता मिल रही है। इस पर सरकारों को नए सिरे से विचार करना होगा। तभी माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता आ पायेगी।

सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में उद्देश्य पूरा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। यह 2009 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध कराना और इसके स्तर में सुधार करना था किन्तु हम इस उद्देश्य से भटक गए, परिणाम यह रहा कि लक्ष्य पीछे छूट गया। हमने तय किया था कि वर्ष 2017 तक यानी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बच्चों की हाजरी शत प्रतिशत होगी और 10 किलोमीटर की परिधि में एक मध्यमिक स्कूल स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2020 तक सभी बच्चों का पंजीयन होना

चाहिए। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 960 नए माध्यमिक स्कूल खोलने और 34311 माध्यमिक स्कूलों को सशक्त बनाने के लिए मंजूरी दी थी। किन्तु इसे हम इसे मूर्तरूप नहीं दे पाए। उसके कारण माध्यमिक शिक्षा का विकास लगभग ठप्प हो गया।

दूसरी ओर 2008 में मॉडल स्कूलों योजना की शुरुआत की गई थी किन्तु यह योजना लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ गई। इस योजना का उद्देश्य गाँवों के प्रतिभाशाली बच्चों को 6000 मॉडल स्कूलों के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल खोला जाना था किन्तु केन्द्र सरकार ने इसमें मदद करने से आगे मना कर दिया और राज्यों से अपने स्तर से चलाने को कहा गया। राज्य सरकारें धनाभाव का बहाना बताकर इस महत्त्वाकांक्षी योजना को आगे नहीं बढ़ा पायी, परिणाम यह रहा कि योजना ने बीच में ही दम तोड़ दिया।

यही नहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने छात्रावास के निर्माण और संचालन की केन्द्र प्रायोजित योजना 2008-09 में शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की और 2009-10 से इस पर अमल होना भी शुरू हो गया लगभग 3500 ब्लॉकों में प्रति ब्लॉक सौ लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू किया गया किन्तु आगे चलकर यह योजना भी ठप्प हो गई जिसके कारण 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की छात्राओं के लिए छात्रावास की स्थापना का भी सपना अधूरा ही रहा। इसके कारण उक्त वर्ग की छात्राओं की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी।

वर्ष 2004 में माध्यमिक स्कूलों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा योजना शुरू की गई ताकि माध्यमिक स्तर के छात्रों को आईसीटी कौशल में क्षमता निर्माण करने और कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रक्रियाओं को सीखने का अवसर मिल सके किन्तु यह योजना भी सही ढर्रे पर नहीं चल सकी क्योंकि जिनके हाथों में इस योजना को मूर्तरूप देने की जिम्मेदारी दी गई थी वो ही बजट का बन्दरबाँट कर योजना को पलीता लगा दिए। यहाँ तक कि स्कूलों में आज तक नियमित कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति तक नहीं की जा सकी है। लैब, कम्प्यूटर के खरीद आदि के लिये जो बजट स्वीकृत किया गया उसका सही उपयोग न होने से तमाम स्कूलों में कम्प्यूटर कमरे में बन्द पड़े सड़ रहे हैं। इसकी पढ़ाई तो दूर की बात है।

माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। अब तक केन्द्र में रही सरकार केवल आँकड़ों पर ध्यान देती रही और उसको देखकर संतुष्ट और खुश भी बनी रही। परिणाम रहा कि समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी रही और बजट हर वर्ष बढ़ता रहा। वर्ष 2014 की सिर्फ रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर. 2014) देखकर हम प्रसन्न तो हो सकते हैं। किन्तु वास्तविक स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। प्रश्न यह है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के वर्षों के प्रयास के बाद भी भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार क्यों नहीं हो सका। गौर करें तो पता चलता है कि सब बुनियादी पहल शिक्षकों की योग्यता का है जिसको हमेशा नजरन्दाज किया गया। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं। इस सवाल पर गौर करने से पता चलता है कि शिक्षकों की चयन प्रक्रिया भ्रष्ट और गैर पारदर्शी है। यहाँ बता दें कि आज शिक्षकों का पेशा काफी आकर्षक और आसान बन गया है। क्योंकि यहाँ वे तभी काफी आकर्षक और सेवा सुरक्षा की भी लगभग गारन्टी है। फिर भी अच्छे और योग्य लोग शिक्षण कार्य में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। इसका अन्वेषण करने के बाद पता चलता है कि चयन प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पैसे के बल पर दोयम दर्जे के लोग तो चयन में सफल हो जा रहे हैं किन्तु योग्य और प्रतिभावान लोग पीछे छूट जाते हैं।

दूसरी ओर शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्तम व्यवस्था नहीं है। जबकि प्रशिक्षण संस्थानों की लगभग सभी राज्यों में भरमार है। प्रशिक्षण पाने के लिए भी अभ्यर्थियों को भ्रष्टाचार से गुजरना पड़ता है। उसके कारण प्रतिभावान लोग प्रशिक्षण में प्रवेश पाने से भी पीछे छूट जाते हैं। प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. अशोक जे देसाई के 'शोधपत्र' प्राब्लम्स ऑफ टीचर एजूकेशन इन इण्डिया के अनुसार सरकारी प्रशासन ने शिक्षकों को शिक्षा के आधुनिक तरीके सिखाने पर कम ध्यान दिया।

बुनियादी ढाँचे की कमी ने तो स्कूली शिक्षा की रीढ़ ही तोड़ दी। हाल में आए अध्ययन के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पेयजल की समुचित व्यवस्था ही नहीं है। लगभग 98 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय नहीं है यदि कहीं है भी तो वह दुरुस्त और पर्याप्त नहीं है। इससे कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इससे छात्रों की क्षमता का विकास सही रूप में नहीं हो पा रहा है। यही नहीं सूत्रों में पर्याप्त भवन और कोष्ठोपराण जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी आज भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान ने काफी बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में किया है।

वर्तमान युग के उदारीकरण वैश्वीकरण एवं निजीकरण ने हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को काफी प्रभावी किया है, उसने तमाम परिभाषाओं को भी बदल दिया है। हम जानते हैं कि विकास के आधारों में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, इसी पर सम्पूर्ण सामाजिक विकास टिका हुआ है। जनसंख्या का शिक्षित होना ही विकास को पोषित करता है क्योंकि किसी भी देश की शिक्षा की स्थिति का सीधा संबंध उस देश की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना से होता है।

अत: स्पष्ट है कि शिक्षा तभी अपने आयामों को छू पायेगी जब वह इन विशेषताओं से पूर्ण हो और सामाजिक सरोकार से जुड़ी रहेगी। ❑

(स्वतंत्र लेखक)

माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारें विद्यालय क्रमोन्नत कर शिक्षा विद्यार्थियों को सुलभ हो इसका प्रयत्न कर रही हैं। परन्तु गुणवत्ता के लिए प्रयत्नों में कमी के कारण अभीष्ठ लाभ नहीं मिल पा रहा है। सम्पूर्ण देश में वित्तीय संसाधनों की कमी, मानकों के अनुरूप शिक्षकों की कमी, विद्यालय-निरीक्षण की अव्यवस्था, नियंत्रण में शिथिलता, शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमियाँ माध्यमिक शिक्षा चुनौतिपूर्ण स्थिति में है। सभी राज्यों में संख्यात्मक दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में छात्र संख्या की स्थिति, प्राथमिक स्तर के ड्राप आउट के बाद भी काफी ठीक पाई जाती है। देश के व्यापक हित में राष्ट्रीय स्तर पर एक मत से शिक्षा नीति निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें राजनैतिक हस्तक्षेप न हो तथा ईमानदारी से क्रियान्विति की जाये।

लीक से हटकर हो शिक्षा व्यवस्था

❑ **बजरंग प्रसाद मजेजी**

विश्वगुरु भारत तक्षशिला और नालन्दा जैसे महान् शिक्षा केन्द्रों की परम्परा का स्वामी होने के बाद भी, भारत का जनजीवन पराधीनता के काल में छिन्न-भिन्न हुआ। वहीं स्वतंत्रता की प्राप्ति के 70 वर्षों पश्चात् भी लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति के बन्धन से सम्पूर्ण शिक्षा जगत छटपटाता हुआ दिखाई देता है। परिणामस्वरूप शिक्षा दिशा-विहीन हो गई है। शैक्षिक परिवेश राजनैतिक हस्तक्षेप का केन्द्र बिन्दु बन गया है। केन्द्र के मानव संसाधन मंत्री तथा राज्य के शिक्षा मंत्रियों की इच्छा और अपेक्षा का विभाग बनता जा रहा है। देश के शिक्षाविदों, शिक्षक और शिक्षक संगठनों से बदलाव या परिवर्तन के लिए रायशुमारी नहीं की जाती है, जिसका परिणाम होता है, योजना या नियमों की क्रियान्विति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। शिक्षा आयोगों का गठन होता है, परन्तु उनकी अभिशंषाओं पर पूर्णत: ध्यान नहीं दिया जाता है। सरकार की दलगत नीतियाँ भी शिक्षा क्षेत्र को बहुत प्रभावित करती हैं। शिक्षक को मात्र मार्गदर्शक/ सूचनाकर्ता माना जाने लगा है। शिक्षक के सम्मान में निरन्तर गिरावट आने लगी है। राष्ट्रनिर्माता की जिम्मेदारी को निर्वाह करने वाले आचार्य को जवाबदेही की कसौटी पर खरा उतरने में कठिनाई अनुभव होने लगी है। वह राजनेताओं के विचारों, आदेशों, नीतियों के क्रियान्वयन का मात्र संवाहक बनकर रह गया है।

स्वतंत्रता के बाद शिक्षा क्षेत्र में जो व्यापक नीति विषयक परिवर्तन होने आवश्यक थे, वे नहीं हुए और शिक्षा का जितना वास्तविक विस्तार होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। परिणामस्वरूप शिक्षा को मुख्यत: सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम ही माना जाता रहा है न कि एक सुनागरिक बनने का। शिक्षा ने संख्यात्मक आँकड़ों में प्रगति की है परन्तु धरातल में अशिक्षित, बेरोजगार, फर्जी डिग्रीधारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था सरकारी एवं बहुसंख्यक निजी शिक्षण संस्थानों के कारण आर्थिक और सामाजिक ढाँचों में अन्तर दिखाई दे रहा है। भौतिकता की अंधी दौड़ और मानव मूल्यों में तेजी से ह्रास होने के कारण नीतियों का ईमानदारी से क्रियान्वयन कठिन हो गया है। जो संसाधन शिक्षा क्षेत्र में जुटाये गये हैं, उनका संतोषजनक लाभ शिक्षा और समाज को नहीं मिल रहा है।

माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न

माध्यमिक शिक्षा स्तर के बालक आयु वर्ग 14-20 सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्तर के होते हैं। बालक के निर्माण में यह आयु बहुत प्रभावी होती है। समझ और नासमझी के भँवर में बालक के

जीवन की दिशा का निर्माण इसी आयु से प्रारंभ होता है। यह अवस्था किशोर वर्ग में मानी जाती है। इस स्तर के बालकों को संस्कार निर्माण एवं जीवनोपयोगी शिक्षा के आधार का ज्ञान देना आवश्यक है। कौशल शिक्षा का प्रारंभिक ज्ञान इसी स्तर पर दिया जाता है। केन्द्र सरकार ने डॉ. लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' गठित किया था। उन्होंने सन् 1835 से 1948 तक की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करके सुधार हेतु सुझाव दिये थे। डॉ. मुदालियर ने कहा कि 'परम्परागत रूप से दिये जा रहे शिक्षण से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। दी जा रही माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा जीवन से कटी हुई है, इससे बालक का विकास संभव नहीं है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी होने के लिये विद्यार्थियों को सुनागरिक बनाना बताया, जो आत्मविश्वास के साथ, जीवनोपयोगी दक्षता प्राप्त कर सकें। इस हेतु आदर्श माध्यमिक विद्यालय की संकल्पना का मूर्तरूप में देने का सुझाव दिया था तथा शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों के सर्वांगीण विकास करना और देश के प्रति जागरूक नागरिक का निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित किया।

माध्यमिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारें विद्यालय क्रमोन्नत कर शिक्षा विद्यार्थियों को सुलभ हो इसका प्रयत्न कर रही हैं। परन्तु गुणवत्ता के लिए प्रयत्नों में कमी के कारण अभीष्ठ लाभ नहीं मिल पा रहा है। सम्पूर्ण देश में वित्तीय संसाधनों की कमी, मानकों के अनुरूप शिक्षकों की कमी, विद्यालय-निरीक्षण की अव्यवस्था, नियंत्रण में शिथिलता, शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमियाँ माध्यमिक शिक्षा चुनौतिपूर्ण स्थिति में है। सभी राज्यों में संख्यात्मक दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा में छात्र संख्या की स्थिति, प्राथमिक स्तर के ड्राप आउट के बाद भी काफी ठीक पाई जाती है। राजस्थान का उदाहरण देखें तो 2017 में बोर्ड वार्षिक-परीक्षा में छात्र संख्या निम्नानुसार रही-

परीक्षा	नियमित	स्वयंपाठी	योग
उच्च मा.	8,54,386	14,745	8,69,131
माध्यमिक	10,928,30	6289	10,99,119
प्रवेशिका	7703	66	7769
वरि.उपा.	3936	65	4001
योग	19,58,855	21165	19,80,020

NCERT के CBSE विद्यालयों, ओपन बोर्ड में बैठने वाले छात्रों की संख्या भी समकक्ष है।

माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक स्तर में कई विषयों को अध्ययन हेतु विधारण किया गया है। पाठ्यक्रम का बोझ बहुत अधिक रखा गया है, जबकि जीवन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु सीमित पाठ्यक्रम होना चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में रखा जाना चाहिए। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भी शिक्षा नीति का निर्धारण न होना देश का दुर्भाग्य है। हम अभी भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के पीछे भाग रहे हैं। देश के व्यापक हित में राष्ट्रीय स्तर पर एक मत से शिक्षा नीति निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें राजनैतिक हस्तक्षेप न हो तथा ईमानदारी से क्रियान्विति की जाये। माध्यमिक शिक्षा के लिए वातावरण बनाएँ, जो वास्तविक ज्ञान, अभिनवन और जवाबदेही को प्रोत्साहन दे सकें।

माध्यमिक शिक्षा स्तर सुधार हेतु सुझाव

बालकों में छिपी प्रतिभा होती है। वे बुद्धिमान, परिश्रमी, योग्य होते हैं। आवश्यकता है उर्जावान शिक्षक बालमन की गहराइयों को जानकर चुनौतिपूर्ण कार्य को सरल बनायें। बालक की क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें तो वह सफल उपयोगी नागरिक बन सकता है। दुर्भाग्य से हमने सफलता की परिभाषा को संकुचित बना दिया है, जिससे कुछ छात्र अपने को सफल बनाते हैं और अधिकांश निराश होकर समाज में अपना उपयुक्त योगदान नहीं दे पाते हैं। हमें समुचित राष्ट्रीय विकास करना है तो बालकों को उचित ढंग से शिक्षित करना ही एक मात्र उपाय है। उर्जावान शिक्षक विभिन्न मानसिक स्तर के बालकों को रोचक विषयवस्तु के साथ प्रभावी विधाओं से शिक्षण कराने वाला शिक्षक सफल शिक्षक कहलाता है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षक के तीन गुण बताये हैं- व्यक्तित्व, आचरण व अध्ययन, शिक्षक की दक्षता प्रतिबद्धता और सकारात्मक सोच से माध्यमिक स्तर के बालकों का भला हो सकता है। सफल शिक्षक को निम्न बिन्दुओं को आत्मसात कर शिक्षण विधा का प्रयोग करना चाहिए-

- शिक्षण के पूर्व वातावरण निर्माण करे ताकि मानसिक रूप से बालक केन्द्रित हो।
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरलतम विधि से प्रस्तुत करे।
- स्नेह, आत्मियता का व्यवहार, समान दृष्टि से बालक के साथ व्यवहार करे।
- मूल्याङ्कन कठोर न हो, आयु रुचि, स्तर के अनुसार किया जाये।
- शिक्षक अपने को व्यवसाय की दृष्टि से हटकर, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाये तथा उचित अवसर, सहायक सामग्री, सूझबूझ, योग्यता और कौशल उपयोग से सफल शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करे।
- भारत में शिक्षा राष्ट्रीय सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए, प्रकृति में जो भी सर्वोत्तम, सर्वाधिक प्रभावी, अंतरंग और जीवनोपयोगी हो उसे व्यक्त कर सके।
- देश के 22 करोड़ विद्यार्थियों में से मात्र 2 करोड़ स्नातक स्तर तक पढ़ने जाते हैं। इसे चुनौती मानकर शिक्षा नीति का निर्धारण करने की आवश्यकता है। ❑

(स्वतन्त्र लेखक)

Higher education for uplifting rural area :

An alternative to Macauley's education system

❑ **Vipul Somani**

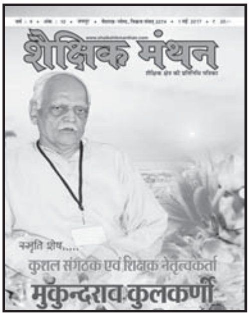

Macaulayism is the conscious policy of liquidating indigenous culture through the planned substitution of the alien culture of a colonizing power via the education system. He was instrumental in the introduction of English as the medium of instruction for higher education in India. "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect.

In India more people live in rural areas than in urban. More and more people want to leave their places and migrate to urban area for livelihood and change their life. The country endowed with vast natural resources and young people are facing a crisis of unemployment and more than that there is a big problem of mindset and values. Successive governments in independent India tried to improve life of rural people and underprivileged classes. A huge amount of money and resources were and being diverted for the upliftment of marginalized classes. It was thought that education is the key for fighting poverty and bringing smile on the faces of people. Unfortunately though there is increase in the spread and level of education yet the rural areas are almost the same as before independence. People have become more dependent on government for various facilities including water, energy and other resources including providing food at subsidized rate or for free. In a strategy of appeasement and creating vote bank, successive governments have been increasingly providing freebees to poor. In our country it is good to be poor as politics of poverty fetches more votes than politics of development where people using their resources become self-reliant.

Macaulayism is the conscious policy of liquidating indigenous culture through the planned substitution of the alien culture of a colonizing power via the education system. He was instrumental in the introduction of English as the medium of instruction for higher education in India. "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects in terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population," Macaulay declared. His education system is responsible for

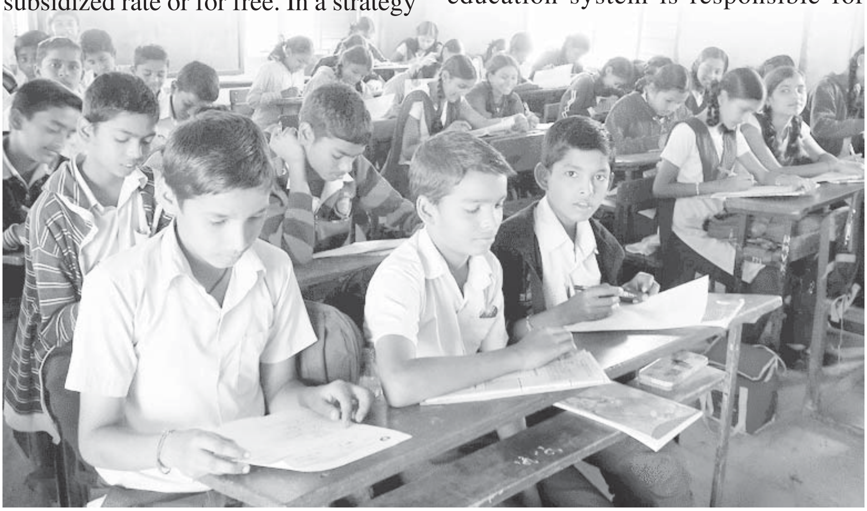

producing generations of Indians not proud of their distinct heritage. It has "marginalize inherited learning" and has uprooted academics from traditional Indian modes of thought, inducing in them a spirit of self-denigration (heenabhavna).

Mahatma Gandhi had dreamed of society that is self-reliant and having self respect. He had envisioned a holistic developed society. For this he had proposed an education system called nai talim or basic education an embodiment of his perception of an ideal society consisting of small, self-reliant communities with his ideal citizen being an industrious, self-respecting and generous individual living in a small cooperative community. In 1937 this was experimented at Wardha under the leadership of Vinoba Bhave who poetically articulated the soul of nai talim as yog (union of individual with divine), sahyog (collaboration), and udyog (meaningful work). He emphasized the importance of humility.

Based on these principles in 1939, nai talim was also implemented in Gujarat at Ambala, in Bhavnagar district. Later in 1953 an institute of higher learning based on the same principles was started at Lok Bharati, Sanosara, in Bhavnagar district. This system of education is a sound alternative to the Macaulay's system of education where in people get educated but for such educated youth there is no work in rural areas. Vinoba Blvae lamented that existing education focuses on book learning and ignores life; it is based on suppressing natural curiosity and cramming knowledge to secure marks and a job; it discourages original thinking; it is fragmented, dualistic, one sided, irresponsible (with no domestic cares), and a chore; neither fulfilling for the students nor the teacher; it is gramophone learning and prepares us for exams which works as purgative. According to him nai talim works on three aspects- a sympathetic heart, a questioning intellect and a hungry stomach.

The Bachelor of Rural Studies (B.R.S.) programme offered by Lok Bharati at Sanosara and various colleges affiliated to different Universities in Gujarat including Veer Narmad South Gujarat University, Surat, fulfils the dream of Mahatma Gandhi. The efforts put in 1953 are still continued. The curriculum of the course develops, committed, enthusiastic and dedicated youth ready to work in rural areas for building a prosperous rural society. The characteristics of the syllabi developed include camps as medium of education, work experience, useful social activities, field laboratories, hands on agriculture and horticulture, animal husbandry, health and hygiene, extension activities. This experiment was successfully repeated in several institutes established as Gram Vidyapiths that are now affiliated to various Universities in Gujarat. One of the characteristic features of the curriculum developed was that apart from the classroom teaching and practicls in the laboratory and agricultural fields every student has to spend 30 days in a village and 90 days internship at institutes directly concerned with rural area. Also they have to write a thesis based on field work conducted during the final semester.

Due to the demand of civil society and NGOs, who initially funded the programme, Mahatma Gandhi Department of Rural Studies was established at South Gujarat University. Looking at the prospects of the Department and the program it offered it later received grants from UGC. The department has been offering 2 years full time post graduate program leading to Masters of Rural Studies (MRS) since 1970.

The graduates and post graduates of Rural Studies are placed in various NGOs and government agencies and live departments. The Government of Gujarat has kept qualification for Gram Sevak (village level extension worker) exclusively as BRS.

Looking at the rural development scenario throughout the country, there is an urgent need of making a special cadre in the Indian Administrative Service for Rural Development, wherein, young, enthusiastic, committed candidates having knowledge about the strength, weakness and opportunities available at rural level are further trained and put into service.

These courses of higher education in rural areas will not only help in development of the most neglected areas but also create sensitivity among the urban population about its traditions and culture. Also it will inculcate a spirit of living with nature under all types of conditions. This system of education can set a reverse trend of sending educated masses to the rural area that are well trained, enthusiastic, having developed core human values and commitment. ❑

(Mahatma Gandhi Department of Rural Studies, Veer Narmad South Gujarat University, Surat)

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अभ्यास वर्ग में दीप प्रज्वलन करते हुए

मध्यप्रदेश शिक्षक संघ प्रान्तीय अभ्यास वर्ग दमोह में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए

मगध विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रतिनिधि सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए

हरिद्वार में महिला संवर्ग के अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग को सम्बोधित करते हुए

महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर महासंघ के सम्मेलन में दीप प्रज्वलन करते हुए

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कन्याकुमारी में दीप प्रज्वलन करते हुए

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक मैसूर में संबोधित करते हुए

दिल्ली में आयोजित उच्च शिक्षा संवर्ग के राष्ट्रीय सम्मेलन में

उच्च शिक्षा संवर्ग का ज्ञापन देने जाते हुए

जयपुर में आयोजित अमृत महोत्सव में प्रो. ललित किशोर चतुर्वेदी से सम्मान राशि प्राप्त करते हुए

महाराष्ट्र राज्य मान्य खाजगी प्राथमिक शिक्षक शिक्षकेत्तर महासंघ के अभ्यास वर्ग को संबोधित करते हुए

केन्द्रीय कार्यालय भवन के गृह प्रवेश अवसर पर संबोधित करते हुए

अ.भा. चिंतन बैठक भोपाल में कार्यकर्ताओं के साथ

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन आगरा में

जन्तर-मन्तर, दिल्ली में धरना प्रदर्शन

विद्यापीठ शिक्षण मंच द्वारा आयोजित प्रथम विदर्भ प्रदेश अधिवेशन

एम.एस.वी.एस.एस. के प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

एम.एस.वी.एस.एस. द्वारा आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री सुब्रह्मण्य स्वामी

पुंछ (जम्मू कश्मीर) में जोन बैठक में संभागी कार्यकर्ता

कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ के कुलपति को ज्ञापन देते हुए

गुजरात के राज्यपाल को सौजन्य भेंट करते हुए रा. संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर साथ में श्री घनश्याम भाई पटेल एवं प्रो. प्रगनेश शाह

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ गुजरात प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारी

गुजरात विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के साथ विमर्श करते हुए

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उ.प्र. की सामाजिक समरसता गोष्ठी में अ.भा. स.संगठन मंत्री श्री ओमपाल सिंह कार्यकर्ताओं के साथ

To become Viswa Guru, Bharat has to give the world what they don't have, and what we have in plenty. That shall be original Bharatiya knowledge for the world. We know that all others already have what may be known as empirical scientific knowledge, and we also know that no one has the knowledge of the transcendental, spirituality and Sanskriti as Bharat has. Precisely this is what we should be providing the world with.

Viswa Guru Bharat : Educating the world

❑ **Dr. TS Girishkumar**

I don't think that there shall be any doubt in the minds of sane people of understanding that knowledge whatever, began in Bharat. It is not only the case that knowledge of all kind began in Bharat, but it is also the case that the process of obtaining knowledge in Bharat began very long ago, indeed into the remote past where we are unable to fix the process of knowing chronologically, as compared with the similar process began in other places. Thus Bharat is not only the forerunner in obtaining man's knowledge, but it is also the case that all others started gathering knowledge a long time after the whole thing began in this land.

A conjecture of chronology

We consider the Vedas to be the very first knowledge texts. We also understand that our knowledge did not get into written form, for long period of time, how long, we are unable to say for sure. But we know of two traditions through which knowledge existed and got transmitted, the traditions of Sruti and Smriti. In simpler terms, it used to be remembering and speaking to the deserving. Things are going to get complicated when we start enquiring more into these Sruti and Smriti traditions, as we will now start coming across the language involved in them. The language of Sanskrit must have got developed gradually, a language that is amazingly capable of compressing knowledge into much smaller words, sentences and texts. May be the concept of 'Mantra' is becoming clearer at this point, Mantra may be expression of highly compressed verses those can unfold volumes of knowledge; provided there is a Guru, Acharya or teacher to do so. In time, though much later, these verses got into written form by established scholars.

What must have been the period of the Vedas? Don't go by the European chronologists, they are actually fooling us in their un-knowledge. If we accept that the Vedas must have been

created at the banks of River Saraswati, as it is generally accepted now, it becomes possible for us to associate the period of the Vedas with the period of Saraswati, when the river was flowing in all her might. From healthy Saraswati to drying up Saraswati must be logically the time span here in question as well. Michel Danino, the French man who became a true son of Bharat writes much about these in his book "The Lost River – On the trail of river Saraswati" which was published by Penguin India in 2010. Michel speaks about some 3700 settlements on either bank of Saraswati, which indeed are the Vedic sites, spanning into three stages as early, medieval and later. Otherwise, by geography, there are some 2500 sites, spreading over 88,000 square kilometres. The area identified is from river Tapi in the south to river Sindhu in the north and from river Ganga in the east to Kutch in the west. The so named 'Indus' Valley is actually Saraswati valley. To fix a chronology of the Vedas, it becomes essential to fix the chronology of river Saraswati.

The importance and significance of the river Saraswati to Bharat is striking. We have many 'Triveni's' in Bharat, and in most cases there are only two rivers present out of three. The third river is implied as river Saraswati. There is also a suggestion that Trivenis are present on the erstwhile path of Saraswati, this is yet to be confirmed though. There is also the suggestion that Saraswati surfaces at given places. Michel Danino also makes an interesting observation about legends of Bharat. He says that instead of recording historical phenomena, the wisdom of Bharat used to create legends and made them afloat, and they remained through generations. Each legend is a Sutra, Cipher, and one has to get the appropriate key to it in order to understand. Here, let me suggest that the period of Vedas shall be the period of River Saraswati.

Methods of obtaining knowledge

We say that the Vedas are knowledge texts, and there shall be no confusion about it. One thing we must try to understand here, what must have been the methods the Vedic people adopted in acquisition of all these tremendous knowledge? We have ancient texts giving us accurate details of present day knowledge, be it Aryabhattiyam or Maharishi Kanada and many more like them. The narrations in those texts are accurate in front of modern empirical scientific knowledge: hence the question arises, how did they know all these? Even glass was invented much later!

Modern science adopts empirical methods of knowing basically through observation and experiment, as well as discovery of causal connection between given antecedent and consequent. Humans depend on their five sense organs to all these, and science invents 'instruments' which basically enhances the natural abilities of five sense organs. Such is the basic programme upon which science goes about its endeavour.

None of these things were neither available to the Vedic people, and none of these were

used by the Vedic people. One stands in need of modern science when one tries to know through the sense organs. Here, the Vedic people developed a method of knowing without the employment of sense organs, their methodology was trans-sensory. When the method of knowing was trans-sensory, empirical science is absolutely unnecessary, and can easily be faulty many a time as experienced by us in many cases. We have another knowledge stream that discusses this trans-sensory knowing.

Yoga is an established school of philosophy in Bharat. There is a core text discussing Yoga, composed by Maharishi Patanjali, and hence Yoga came to be called Patanjali Yoga, apart from many other texts. This text is available to the world. Yoga discusses trans-sensory perception, or knowing as Yogic perception or 'Yogaj'. Yogaj is directly knowing, and is often called 'Anubhava' directly experiencing, and hence becomes experiential.

Now we have ancient Bharatiya texts discussing things with subtlety and accurately, we know about a method to obtain such knowledge. How come it is still difficult for the world to accept such things? It is only a matter of common sense for the world to accept this logically. Here we also fail: we hardly do anything to make such things available to the world. Thus it is our ignorance combined with their ignorance that these things are hardly known.

A possible sequence of knowledge obtaining

Here I am about to speculate, trying to be as logical as I can. Vedas are said to be 'experiences' of the Maharishis. Indeed it is Experience as Anubhava. At once this puts Yogaj and Yogavidya before the Vedas. If the knowledge is obtained through Yogaj, then Yoga must have preexisted. This also makes it mandatory for any student seeking knowledge to practice Yoga prior to starting their training in acquiring knowledge, and this suggests how both Sruti and Smriti used to be so commonly natural to those scholars. This also explains why they were all Yogis and Maharishis. In other words, an Acharya of the ancient times was necessarily a Maharishi. Subsequently, in later days, Maharishi Patanjali must have composed the Yoga philosophy into written form from Smriti along with his team of Acharyas. This must have the case also with Maharishi Vyasa, who composed the Vedas from Smriti along with his team in 'Naimisharanya'.

Further, this knowledge tradition gave rise to the Bharatiya Sanskriti: and as transcendental development took place, it also gave rise to Dharma, the Vedic Dharma, which we call today as the Hindu Dharma. Gurukulas or universities must have developed as a corollary to these things, and it was just natural for anyone seeking knowledge to reach such Gurukulas to learn.

The composition of Vedas are such that they cannot be understood other than through an Acharya. Maharishi Aurabindo finds this as very deliberate, so that the knowledge shall not go to wrong hands. And what is more, they were very successful from preventing this knowledge from going into wrong hands. Nonetheless, the strong Vedic influence on other religions of the world may create some doubts: which is easily understood as the scholars travel to Bharat to learn and they in turn teaching others who look for knowledge.

Upanishads

Later, Acharyas felt the need of bringing out philosophical aspects from the Vedas into simpler versions for the needy. They brought out the Upanishads in as simple manner as possible. They tried presenting complicated phe-

nomena through stories and dialogues, as conversations. Something like presenting a drama or play. That is why one finds each Upanishad belonging to one of the four Vedas.

The influence of Vedic knowledge on Greek knowledge tradition must not go unmentioned. The influence of Vedic Dharma on Greek Hellenistic religion, the influence of Upanishadic methods of dialogues in Plato writing his dialogues, the influence of Varnashrama Dharma on Plato's ideal society etc. are few of the detail indicators.

Educating the world

In due course of time, innumerable Gurukulas or Universities got set up in Bharat, where people from all over the world came to learn. We do not know details of these Gurukulas, except the very popular ones like Takshasila. Perhaps one of the reasons for the popularity of Takshasila was its location, at the frontier, easily accessible to the European world. But Bharat also had other points of access both from sea and through mountains, and there also could have been many Universities both smaller and bigger. People came from all directions using all means of transportation, not just the old silk route alone.

Further comes the period of Buddha, by when Hindu Gurukulas must have become caste ridden and coming down. Precisely, that was the need of Buddha as well as the role of Buddha by way of refining Vedic Dharma. When Varnashrama Dharma is misunderstood as caste system, the whole Vedopanishadic knowledge tradition was slowly collapsing. Knowledge is to be put in front of all, and then we choose the right and deserving ones to go ahead in knowing. We will keep getting great minds to train. But when we select people in whose front we put knowledge, we get lesser people, and from them, lesser scholars, obviously.

Buddha just did the right thing. He put the same Vedopanishadic knowledge tradition in front of everyone, and that too in common people's language without mentioning that they are the Vedas and Upanishads. From this came the great tradition of Buddhist Acharyas, Shramanas and such mighty scholars. They continued the Gurukula practice of teaching and learning and kept attracting knowledge seekers from all over the world. Nalanda is only one such example. We don't know how many such Gurukulas existed through the one thousand years of Buddhism, but I know that my small village in the south used to be one such Gurukula known as 'Srimulavasa'. (it is my father who first told me about this in childhood). Obviously, people from all over must have been swarming these places for long times.

Sankaracharya

It shall be inappropriate to

conclude a discussion about Buddhist Universities without bringing in Jagadguru Adi Sankaracharya. We know that Sankaracharya's Guru (Govindabhagavadpada) and his Guru (Gaudapada) are both Buddhist Acharyas. Still, we see Sankaracharya as the one man army who re-established the glory of the Vedopanishadic knowledge tradition, and just with his roughly thirty years of living, Buddhism vanished from Bharat.

It may apparently be difficult to understand this phenomenon of Buddhism vanishing from Bharat in such a short time. Sankara did just one thing only: he entered into discussions with Buddhist Acharyas throughout Bharat and demonstrated to them what originally Buddha intended and did. The Buddhist Acharyas realised that all those they had been thinking as original to Buddha are nothing other than from the Vedopanishadic knowledge tradition. In complete and enviable intellectual honesty and integrity, it was natural for them to go back to the Vedopanishadic knowledge tradition as spontaneously as possible. With this, the Buddhist Acharyas got rightly and better located into the Vedopanishadic knowledge tradition. Naturally, there was no need of a separate Buddhism to the scholar's minds, and Buddhism went out of Bharat. One may look at this phenomenon as the great Hindu amalgamation.

Educating the world

In retrospect, we see that it ever was the function of Bharat to educate the world. In the ancient times, we only used to have the knowledge and we did impart our knowledge to the desiring and deserving profusely.

Times do change and times had changed. Empirical way of knowing developed and emerged as science, and European world had made tremendous growth as well as achievements. Our Nation also had to undergo very harsh as well as hard times for long centuries of long time, and our established knowledge system as well as tradition got mutilated. This made our first phase of knowledge tradition far flung from common experience of common people.

With the second phase of knowledge tradition, we find ourselves imitating and copying the other worlds, which are supposed to be empirically developed. It would make sense for us to ask the question, whether or not empirical development is development of total existence, but let that remain for the time being. Bharat can never become what it used to be, the Viswa Guru, with copied knowledge or imitated knowledge of what Europe had already done better.

To become Viswa Guru

To become Viswa Guru, Bharat has to give the world what they don't have, and what we have in plenty. That shall be original Bharatiya knowledge for the world. We know that all others already have what may be known as empirical scientific knowledge, and we also know that no one has the knowledge of the transcendental, spirituality and Sanskriti as Bharat has. Precisely this is what we should be providing the world with.

There shall always be transcendentally inclined minds in any society, and Bharat shall have such minds in abundance. We must focus on such minds and train them to be the representatives of Bharatiya Sanskriti for the whole world. Whether such people shall physically remain themselves within Bharat or somewhere outside does not matter, the seekers will reach them. However, this is an ongoing phenomena in macro – personal level by some, and what we must do is to make it organised and more powerful.

Earlier it used to be the Gurukulas or universities where people arrived to know. At the moment, our present universities are not ready to accept transcendental seekers, though we all could do much better than what is getting done. In one word, we must go into concentrating more on Philosophy and other humanities in our universities. Ironically, I see many people counting the authenticity of many departments in terms of empirical and instant outputs. People with vision can't do such things.

To sum up, we must be able to provide what we have, and we must develop what we have so that we can provide. This at once suggest that we must work into this area of developing what we got from the ancestors and make it available, first among our own people who might be interested and then to others who shall come looking for. I need not to repeat on the area those we ought to and must develop, perhaps people of Bharat know such things better. ❑

(Professor of Philosophy, The Maharaja Sayajirao University of Baroda)

भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण

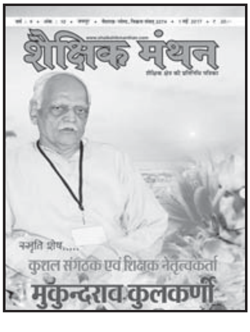

पाश्चात्य भौतिक जीवन के विपरीत हिन्दू दर्शन एवं सनातन संस्कृति ने त्यागमयी चिंतन से हरित जीवन अंगीकार किया क्योंकि प्रकृति का शृंगार भोग से नहीं त्याग से संस्कारक्षम एवं अक्षय रहेगा। अत: पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण जीवन निर्वहन होगा। इसलिए ऋषियों ने समाज को नई दिशा का बोध कराया और भोग की प्रवृत्ति को नकारा और इसे परिग्रह का विस्तार कहकर त्याग से अपरिग्रह की सृष्टि की। पाश्चात्य प्रवृत्ति ने जहाँ हिंसा को जन्म दिया, वहीं भारतीय संस्कृति महनीय त्याग जीवन से शान्ति का अन्वेषण किया। पाश्चात्य की परिग्रह विषमता द्वारा जीवन को अंधकारमय बनाया है तो वहीं भारतीय संस्कृति में अपरिग्रह ने विषमता के युग को निर्मूल किया है।

❑ **डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि'**

यदि हम संस्कृति की बात कहीं भी करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे दृष्टिपटल और मानस में भारतीय संस्कृति की परिव्याप्तता और शुचितापूर्ण महनीय आवश्यकता पर ध्यान जाता है। संस्कृति का सीधा अर्थ भारतीय जीवन और जीवन-मूल्यों में प्रकट होने लगता है। संस्कृति व्यक्तित्व संस्कार की अक्षय प्रज्ञापी है जहाँ पर कुत्सित विचार पावनत्व में परिणत हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृतियों की जाया है यही संस्कृतियों की हिमाद्रि उद्गमा एवं महोदधि में समाधिस्थ चिरन्त है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं की संख्याँकलन करना असम्भव है परन्तु दो टूक शब्दों में ज्यादा स्पष्ट होगा कि "जो भारतीय संस्कृति में है वह कहीं-कहीं मिल सकती है किन्तु जो भारतीय संस्कृति में नहीं है वह कहीं नहीं हो सकता है।

भारतीय संस्कृति और पर्यावरण में गहरा तादात्म्य सन्नद्ध है। मनुष्य अपने जीवन में प्रकृति के साथ मेलजोल बनाकर रखता है। यद्यपि मनुष्य का प्रकृति से सामञ्जस्य आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और पर्यावरण को काफी महत्त्व दिया गया है। प्रकृति के साहचर्य में मानव का जीवन कल्याणमयी रहता है। मनुष्य जहाँ भी रहेगा, वहाँ प्रकृति और पर्यावरण के बिना जीना असम्भव है क्योंकि प्रकृति जीवन के लिए आवश्यक है और इसके उपांग-पेड़-पौधे वन-पहाड़, नदी-झील हमारे जीवन एवं प्राण के लिए सहायक है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा पेड़-पौधे हमारे कार्बनडाई-आक्साइड को ग्रहण करके शुद्ध वायु आक्सीजन के रूप में प्रदान करते हैं।

आज पर्यावरण की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं पर मनुष्य का ध्यानाकर्षित नहीं हो रहा है जबकि प्रदूषित वातावरण से प्राकृतिक जैव-विविधता का निरन्तर क्षरण होना तय है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का जीवन भोग-विलासिता एवं भौतिकवादी सुख की ओर अग्रसर हो रहा है और मशीनीकरण की दुनिया ने जीवन को ही नहीं तबाह किया है अपितु पर्यावरण को भी असुरक्षित कर दिया है, जिसका मूल पाश्चात्य सभ्यता एवं निर्मम दोहन-पद्धति और अत्याधुनिकता की चरम स्थिति है। इन प्राकृतिक संसाधनों के शोषण से समाज कालग्रास बनता जा रहा है और नित्य-प्रति पर्यावरण के संकट की घंटी बज रही है। पर्यावरण को विनष्ट करने के द्योतक कारणों में प्रमुखतम संसाधनों का जर्जर होना और प्रदूषण ही है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी का तापमान-क्वथनांक एवं हिम-गलनांक उत्तरोत्तर तीव्रतायी बनता जा रहा है। नि:संदेह इन्हीं कारणों से प्राकृतिक आपदा एवं विनाशलीला बढ़ रही है। आज हम प्रकृति प्रदत्त सभ्यता का अनुकूल नहीं होकर उसके प्रतिकूल जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। इन सबके मूल में प्रकृति के स्रोतों तथा उत्पादों का पश्चिमीकरण है।

भारतीय संस्कृति ने प्रकृति को शस्य श्यामला बनाकर हजारों शताब्दियों से परिवृन्हित एवं संयोजित किया है। प्रकृति और पर्यावरण के

क्षेत्र में भारतीय ऋषियों–मुनियों में व्यापक दृष्टि व्याप्त थी। इन्होंने आकाँक्षा, अभिलाषा को संकुचित करके पर्यावरण को क्षरण से बचाया एवं अन्त:करण की शुद्धि से आन्तरिक विकास पथ का अन्वेषण किया और परोक्ष में पर्यावरण विकास एवं संतुलन को स्थायित्व प्रदान किया। प्राकृतिक संसाधनों का अल्प सीमित प्रयोग कर इसका संरक्षण भी करते रहे जिससे प्राकृतिक चक्र जीवनानुकूल व प्रवाहमान रहा–

ऊँ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षशान्तिः पृथ्वीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेदेवाशान्ति ब्रह्मशान्तिः सर्वःशान्तिः शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि (यजुर्वेद शान्त्याध्यायः)

पाश्चात्य भौतिक जीवन के विपरीत हिन्दू दर्शन एवं सनातन संस्कृति ने त्यागमयी चिंतन से हरित जीवन अंगीकार किया क्योंकि प्रकृति का श्रृंगार भोग से नहीं त्याग से संस्कारक्षम एवं अक्षय रहेगा। अत: पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण जीवन निर्वहन होगा। इसलिए ऋषियों ने समाज को नई दिशा का बोध कराया और भोग की प्रवृत्ति को नकारा और इसे परिग्रह का विस्तार कहकर त्याग से अपरिग्रह की सृष्टि की। पाश्चात्य प्रवृत्ति ने जहाँ हिंसा को जन्म दिया, वहीं भारतीय संस्कृति महनीय त्याग जीवन से शान्ति का अन्वेषण किया। पाश्चात्य की परिग्रह विषमता द्वारा जीवन को अंधकारमय बनाया है तो वहीं भारतीय संस्कृति में अपरिग्रह ने विषमता के युग को निर्मूल किया है। पाश्चात्य की भोगवादी दृष्टि ने प्रकृति का दोहन करके पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाया तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की अनुपम त्याग ने पर्यावरण का संरक्षण कर मानव के लिए निरन्तर लोक मांगलिक बनाया है। इस संस्कृति ने भौतिक दर्शन को प्रकृति से तादात्म्य एवं साहचर्य का पथ–प्रर्दिशत किया है। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा था–

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः।

भारतीय संस्कृति ने प्रकृति के साहचर्य से रागात्मक सम्बन्ध सिखाया। प्रकृति को पाश्चात्य दृष्टि से न देखकर इसे जननी की संज्ञा दी और इसके कर्त्तव्य को मातृत्व भाव से ऊपर बताया जो हमारे समाज के सभी प्राणियों में स्नेह भाव रखती है तथा इनका लालन–पालन भी करती है। ईशावास्योपनिषद् में इसी के प्रति अनन्य त्याग बताया गया है–

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंञ्च जगत्यांजगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम्।।

भारतीय संस्कृति ने जनता को प्रकृति के प्रति बोधगम्यता की दिशा प्रदान की है और इनके धर्म के प्रति आस्था, विश्वास, परम्पराएँ, पूजा अर्चना का समावेश किया। दैनन्दिन जीवन में भारतीय संस्कृति उत्कृष्ट मानदण्डों पर आचरण एवं संस्कारों का नियमन किया जिनका सीधा सरोकार पर्यावरण के संतुलन पर केन्द्रित है। उन मानवीय मूल्यों ने वन–संरक्षण कर भूक्षरण को अवरुद्ध किया हैं और इससे जलवायु को अक्षय–दान मिला। भूमि वैभवयुक्त करके विनाशजन्य वर्जनाओं से भारत में जैविक विवधताओं को संरक्षण प्रदान किया भारतीय संस्कृति ने मानव को प्रकृति के प्रति श्रद्धा एवं पूजाभाव से युक्त किया। प्रकृति की संतानों- गाय, बैल, कुत्ता, बकरी, सर्प, जीवों, तोता, मैना, कोयल, मोर आदि पक्षियों; आम, पीपल, बरगद, नीम, केला, बांस आदि पेड़–पौधों और औषधि के रूप में वनस्पतियों को जीवन का तादात्म्य बनाकर इसे पूजनीय सिद्ध किया और श्रद्धा–समर्पण का भाव जागृत हुआ। प्रकृति रूप में नदी, समुद्र, पहाड़, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, वायु अस्त्र–शस्त्र, उपकरण, वाहन–साधन, लौकिक व्यवहार की वस्तुएँ आदि जो मानव जीवन में नित्य–प्रति प्रयोजनीय हैं उन्हें देवी–देवता एवं अभ्यर्चनीय बताकर भोग एवं दोहन से दूर रखा। इन्हें आस्था और धर्म से जोड़ देने पर मानव पाप–पुण्य के अनुसार अपने पर नियन्त्रण

रखता है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता है; जिससे पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहायक हुआ। आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों, विधि विधानों एवं पुण्य-पाप की अवधारणाओं को भारतीय संस्कृति ने जन्म देकर पर्यावरण की अनन्य सेवा की है। वृक्ष को काटने वाले को पापी कहकर उसे पाप का भागीदारी बनाया है और इसे अधोगामी कहा, क्योंकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष की तुलना दस पुत्रों के समतुल्य बताया गया है।

दशवृक्षसमावापी दशवापी समोह्नदः।
दशह्नदसमोपुत्रो दशपुत्र समोद्रुमः।।

भारतीय ऋषि वनों में जाकर घोर तपस्या करते थे क्योंकि जीवन की सुख-शांति प्रकृति की सौम्य, रमणीक स्थलों में ही सम्भव होती है। भारतीय वाङ्मय का विहङ्गम दृष्टि से आलोडन करने पर हमें पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति भारतीय संस्कृति की संचेतना एवं जागृति व्यापक रूप में दृष्टिगोचर होती है।

वेदादि सहित अन्य आदिम ग्रन्थों से लेकर आधुनिक ग्रन्थों में प्रकृति-तत्व का उल्लेख मिलता है जिसमें पृथ्वी को माता एवं आकाश को पिता बताया गया है। परिवार में जो माता-पिता के प्रति श्रद्धा-समर्पण होता है वैसी ही भावना प्रकृति के साथ भारतीय संस्कृति ने ही जन्म दिया है। इसने प्रकृति के प्रति भावनात्मक, आध्यात्मिक, धार्मिक-बंधनों और संरचनाओं से गुम्फित करके पर्यावरण की रक्षा के लिए करणीय उत्कृष्ट कर्त्तव्य, वर्जना पूजा और विश्वास धर्म को जाग्रत किया।

पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं से ही प्रकृति के कल्याण के लिए यज्ञादि क्रिया का धार्मिक मानदण्ड रखा जो पूर्णतः विशुद्ध एवं विज्ञान संगत है। क्योंकि औद्योगिक गृहों से निकला धुँआ वर्षा के लिए सहायक न होकर हानिकारक सिद्ध होती है यद्यपि यज्ञादि क्रिया से निर्मात धूम्र पर्जन्य-बादल बनकर आकाशीय वर्षा करते हैं और वायुमण्डल को प्रदूषणहीन बनाने में सहायक है। केवल इसी संस्कृति ने जीव-जन्तु को देवी-देवता के गण एवं वाहन;, पेड़-पौधों में देवी-देवताओं का निवासस्थल; वनस्पतियों में औषधितत्त्व बताकर इनमें श्रद्धा-पूजा की भावना को जाग्रत किया जो जीवन में अत्यन्त उपादेय है क्योंकि इन सबके उपभोग पर नियन्त्रित धर्म की मर्यादा प्रकृति को शाश्वत चिरन्तन और सनातन बनाता है। गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं-

धर्माऽविरोद्धोभूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ।।

अर्थात् जहाँ भोग, धर्म की अवमानना नहीं करता है तो वह दिव्य है। भारतीय संस्कृति ने उपभोग को निषेधात्मक बताकर प्राकृतिक पर्यावरण का अस्तित्व प्रभावित नहीं होने दिया और निरन्तर इनका संरक्षण करता रहा।

प्रकृति की शस्य श्यामला गोद में सादा जीवन सदा प्रफुल्लित और सृजन की सुखद अनुभूति प्रस्फुटित होती है। भारतीय संस्कृति इनको व्रतों एवं त्यौहारों के रूप में उत्सव मनाती है। नवरात्रि, आषाढ़ी पूर्णिमा (वरषाइत) शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली, मकरसंक्रान्ति और ग्रहण दिवस प्रकृति की विशिष्टता को पुनर्स्मरण कराती है। इनसे सौंदर्यानुभूति और अगाध आनन्द से दुःख-सुख के जीवन में सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। भारतीय संस्कृति प्रकृति को ईश्वर की अनुपम सौंदर्यमयी कृति मानती है निरन्तर सूर्योदय, सूर्यास्त, दिन-रात, पहाड़, झरना, वृक्ष, फल-पूसल, धुँआ की सौंदर्य छटा जीवन के अन्तस्तल को परम रागायित कर देती है। ❑

(विभागाध्यक्ष एवं सहायक आचार्य, प्रयोजन मूलक हिन्दी विभाग, सरगुजा विश्वविद्यालय)

MSVSS Meet Chief Minister of Gujrat

A delegation of MSVSS Shaikshik Sangh, Baroda, Gujarat meet the Honourable Chief Minister of Gujarat Shri Vijay Rupaniji and apprised him about the long-pending issues of College and University teachers and non-teaching staff. Issues related to the development and infrastructure of the university were also discussed. The delegation presented a written communication to him in this regard. The Honourable Chief Minister listened to the delegation patiently and assured that the Govt of Gujarat would address these issues on a priority basis and try to solve them. Shaikshik Sangh Gujarat is grateful to the Honourable Chief Minister for his kind concern and support.

KRMSS Meet V.C. of KUD

Karnataka Rajya Mahavidyalaya Shaikshik Sang (R). Meeting with V.C. Registrar, Registrar (Evaluation), Karnataka University of Dharwad, “about practical examination.“ For this Sem. exam. overlapping of afternoon session accepted oraly, “Also positive response to our all following demands.“ Thanks to KUD authorities, members who are actively participated in discussion and also those who are given moral support

मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्र.बा.गजेन्द्रगडकर के बडे भाई एलफिंसटन महाविद्यालय के प्राचार्य थे। वे बाबा साहब के कालेज सहपाठी थे। सन् 1912 में दोनों बी.ए. की परीक्षा में एक साथ उत्तीर्ण हुये थे न्यायमूर्ति प्र.बा.गजेन्द्रगडकर के बडे भाई प्राध्यापक अश्वत्थाचार्य बालाचार्य गजेन्द्रगडकर को सिद्धार्थ महाविद्यालय का पहला प्राचार्य का पद ग्रहण करने का आग्रह बाबा साहब ने किया। प्राध्यापक अ.बा. गजेन्द्रगडकर ने एलफिंसटन महाविद्यालय से समय पूर्व सेवानिवृति लेकर बाबा साहब के निवेदन को स्वीकार किया। बाबा साहब की विशाल ह्रदयता का उपरोक्त उदाहरण है। बाबा साहब के ह्रदय में ईर्ष्या, द्वेष, कटुता का लवलेष भी स्थान नहीं था उनका स्वभाव सभी को साथ लेकर चलने का था। बाबा साहब का कार्य स्वदेशाभिमानी, मानवतावादी था। बाबा साहब के कार्य का मूल्यांकन उनकी ऊँचाई का होना चाहिए।

डा.अम्बेडकर के जीवन के अनछुए प्रसंग

❑ **सीताराम व्यास**

गत अनेक वर्षों से तुच्छ राजनीतिक गतिविधि के बढ़ते विस्तार ने हमारे राष्ट्रनायकों के जीवन चरित् के बारे में जनमानस में दूषित विचार फैलाने का प्रयत्न किया, उनमें डा.अम्बेडकर प्रमुख हैं। उन्हें एक जाति या वर्ग विशेष तक सीमित कर दिया । इससे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँची है। उनके अनुयायियों ने समाज में एक पक्षीय विचार रखकर बाबा साहब को एक चौखट में बन्द कर दिया। जबकि डा.अम्बेडकर एक चरम कोटि के राष्ट्र भक्त एवं सामाजिक समरसता के अग्रदूत थे। वे हिन्दू समाज में व्याप्त विषमता और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उनका जीवन वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय प्राप्त कराने के लिये संघर्षरत था।

आज सुखद अनुभव है कि बाबा साहब की जयंती को देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उनके बारे में व्याप्त धारणा कि वे भारत की सनातन परम्परा के घोर विरोधी थे, ऐसा मानने वाले उनके साथ न्याय नहीं कर रहे है। मेरा लेख इस मिथक को तोड़ने का प्रयास है जो कि तथ्यात्मक घटनाओं पर आधारित है।

यह सर्वविदित है कि डा.अम्बेडकर जी भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा में प्रत्येक विषय पर बहस होती थी और विभिन्न समितियों के सुझाव पर भी चर्चा होती थी। ऐसा ही प्रसंग है राष्ट्रभाषा एवं राज्य व्यवहार की भाषा पर संशोधन सुझाये जा रहे थे। संस्कृत को राष्ट्र एवं राज्य व्यवहार की भाषा पर डा.अम्बेडकर, लक्ष्मीकांत मैत्र, टी.टी.कृष्णमाचारी, डा.बालकृष्ण केसकर व प्रो.नसीरूद्दीन अहमद ने संविधान समिति को सुझाव दिया । जब इस विषय पर संवाददाताओं ने बाबा साहब, से पूछा तो उन्होंने कहा "what is wrong with sanskrit" (संस्कृत में दोष क्या है) प्रो. नजीररूद्दीन ने विदेशी विचारकों के उद्धरण देकर संस्कृत भाषा की अतुलनीय समृद्धि व शुद्धता के बारे में ग्रीक व लैटिन भाषा से श्रेष्ठ है। मगर दुर्भाग्य है कि डा.अम्बेडकर जी द्वारा संस्कृत भाषा के विषय में सुझाये गये संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया।

इस सन्दर्भ में एक आश्चर्यजनक एवं सुखद प्रसंग भी है। संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा पर विभिन्न समूहों में चर्चा चल रही थी। तब लोगों को देखकर आश्चर्य हुआ कि डा.अम्बेडकर व लक्ष्मीकान्त मैत्र शुद्ध संस्कृत में चर्चा कर रहे थे। बाबा साहब की इच्छा थी कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने के विषय में शेतकरी का. फेडरेशन प्रस्ताव पारित करे। किन्तु बी.पी. मौर्य जैसे तरुण कार्यकत्ताओं के विरोध के कारण सम्भव न

हो सका। बाद में च.मू.कृष्णशास्त्री से चर्चा करते समय बी.पी.मौर्य ने इस विषय में खेद प्रकट करते हुए कहा कि हमने उस समय डा.अम्बेडकर जी के संस्कृत भाषा के प्रस्ताव का अकारण ही विरोध किया।

कुछ विचारकों ने अपने लेखों में डा.अम्बेडकर जी को ब्राह्मण विरोधी बताया। उनके लेखन एवं भाषणों का अध्ययन करने से जानकारी मिली कि बाबा साहब ने सदैव ब्राह्मण वृति का विरोध किया पर कभी भी ब्राह्मण जाति का तिरस्कार करने के लिए प्रवृत नहीं हुए।

बाबा साहब का उपनाम अम्बेडकर है जबकि उनके कुल का नाम सकपाल था पर आंबवडे ग्राम के नाम से उनके कुल ने आंबवडेकर उपनाम रख लिया। ''बाबा साहब के छोटे आत्मचरित् में उनका संस्मरण है। उन्होंने लिखा कि मेरे विद्यालय में अम्बेडकर नाम के ब्राह्मण शिक्षक थे। वे मुझे को अपने साथ बैठाकर भोजन कराते थे। उन शिक्षक महोदय ने आंबवडे अर्थ अच्छा न होने के कारण मेरा उपनाम बदलकर अम्बेडकर किया और विद्यालय के रजिस्टर में भी लिख दिया।''

जब बाबा साहब कक्षा छ: के विद्यार्थी थे तब पेढ़से नामक शिक्षक पढ़ाते थे। वे भी बाबा साहब से स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे। एक दिन वर्षा हो रही थी। बाबा साहब विद्यालय पहुँचे तो बुरी तरह से तरबतर हो चुके थे। शिक्षक महोदय ने अपने लड़के के साथ इन्हे घर भेजा। वहाँ गरम पानी से नहलाया तथा सूखे वस्त्र पहनने को दिये।

मुम्बई के एलफिंसटन हाई स्कूल में एक दिन शिक्षक ने भीमराव को श्याम पट पर लिखने के लिये कहा। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों ने ऐतराज किया कि श्याम पट के पीछे हमारे भोजन के डिब्बे रखे है, भीमराव के लिखने के स्पर्श दोष से डिब्बे दूषित हो जायेगे। गणित शिक्षक ने विद्यार्थियों को कहा कि भीमराव श्यामपट पर लिखेंगे, आप अपने डिब्बे उठा लो। गणित के शिक्षक ब्राह्मण थे। इस घटना का उल्लेख भालचन्द्र फड़गे की पुस्तक डा.अम्बेडकर- 1985 में उल्लेख है।

विल्सन हाईस्कूल के ब्राह्मण मुख्याध्यापक कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर ने बगीचे में एक बालक को मनोयोग से पढ़ते देखा। केलुस्कर जी ने बालक भीम से परिचय किया। बाबा साहब ने बताया कि केलुस्कर के वार्तालाप ने मेरे विचारों और जीवन को प्रभावित किया। महार जाति का पहला लड़का हाई स्कूल में अच्छे अंकों से पास हुआ। सन् 1907 में बालक भीम का प्रकट सभा मे सम्मान किया गया। उस सभा में केलुस्कर जी भी वक्ता थे। केलुस्कर जी ने अपनी लिखी 'बुद्धचरित्' पुस्तक पुरस्कार स्वरूप बालक भीम को भेंट में प्रदान की, बालक भीम ने समय न गँवाते हुए उसी दिन पुस्तक पढ़ डाली। इस कथन में अतिश्योक्ति न होगी कि केलुस्कर जी की लिखित पुस्तक ने भीमराव के मन में बुद्ध मत स्वीकार करने का बीज अंकुरित कर दिया। केलुस्कार जी के प्रयास से भीमराव को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति महाराजा गायकवाड़ से प्राप्त हुयी।

महाड़ के चावदार तालाब सत्याग्रह आन्दोलन में बाबा साहब के साथ पी.पी.जोशी ने कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया। महाराष्ट्र के दो ब्राह्मणेत्तर नेताओं ने बाबा साहब के आन्दोलन का समर्थन का प्रस्ताव इस शर्त पर रखा कि वे ब्राह्मणों को आन्दोलन में सहभागी न बनायें। बाबा साहब ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सारे ब्राह्मण अस्पृश्यों के विरोधी है, बाबा साहब को मान्य नहीं था। वे ब्राह्मणवृति के खिलाफ थे। उनका कहना था कि महत्त्व जन्म का नहीं गुणों का है।

बाबा साहब हिन्दू कोड बिल बनाने के पक्षधर थे। उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। डा.राजेन्द्र प्रसाद ने भी इस बिल का विरोध किया। ऐसे समय में दो ब्राह्मण डा. हृदयनाथ कुंजरू वि.न. गाडगिल ने लोकसभा में हिन्दू कोड बिल का मुक्त हृदय से समर्थन किया। यही वि.एन. गाडगिल अस्पृश्यों के साथ पुणे के एक मन्दिर में जबरन प्रवेश के प्रयास में घायल हो गये।

मुम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्र.बा.गजेन्द्रगडकर के बडे भाई एलफिंसटन महाविद्यालय के प्राचार्य थे। वे बाबा साहब के कालेज सहपाठी थे। सन् 1912 में दोनों बी.ए. की परीक्षा में एक साथ उत्तीर्ण हुये थे न्यायमूर्ति प्र.बा.गजेन्द्रगडकर के बडे भाई प्राध्यापक अश्वत्थाचार्य बालाचार्य गजेन्द्रगडकर को सिद्धार्थ महाविद्यालय का पहला प्राचार्य का पद ग्रहण करने का आग्रह बाबा साहब ने किया। प्राध्यापक अ.बा. गजेन्द्रगडकर ने एलफिंसटन महाविद्यालय से समय पूर्व सेवानिवृति लेकर बाबा साहब के निवेदन को स्वीकार किया। बाबा साहब की विशाल हृदयता का उपरोक्त उदाहरण है। बाबा साहब के ह्दय में ईर्ष्या, द्वेष, कटुता का लवलेष भी स्थान नहीं था उनका स्वभाव सभी को साथ लेकर चलने का था। बाबा साहब का कार्य स्वदेशाभिमानी, मानवतावादी था। बाबा साहब के कार्य का मूल्यांकन उनकी ऊँचाई का होना चाहिए। केवल शब्दों के अलंकारो से नहीं। उनकी महानता की कसौटी "the length of one's shadow on future"

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक स्व.श्री गुरुजी ने सन् 1962 में बाबा साहब की 73 वीं जयन्ती के निमित्त एक पत्रिका के विशेषांक में मार्मिक सन्देश लिखा ''----------मेरी ऐसी श्रद्धा है कि आज भी डा.बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के भले के लिए, धर्म के हित के लिए, अपना चिरंजीव समाज निर्दोष व शुद्ध बनें, इस दृष्टि से कार्य किया न कि समाज से विलग होने के लिए। इसलिए इस युग के भगवान् बुद्ध के उत्तराधिकारी के नाते उनकी पवित्र स्मृति को अन्त:करण पूर्वक अभिवादन कर रहा हूँ।'' ❑

(सेवानिवृत्त प्राध्यापक रोहतक, हरियाणा)

क्या परीक्षा से ही बच्चों का आकलन सम्भव है

❑ अशोक चतुर्वेदी एवं विनित जोशी

पहले 10 वीं बोर्ड परीक्षा आधे में वैकल्पिक थी और आधे में अनिवार्य थी। 60 प्रतिशत बच्चे बोर्ड परीक्षा नहीं देते थे। कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन (सीसीई) का सिस्टम लागू था, जिसके तहत जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देते थे उनका आंतरिक आँकलन होता रहता था। यह 10वीं में लागू था। अब सभी स्कूलों में 10वीं बोर्ड की परीक्षा एक जैसी होगी। इसी तरह छठी से आठवीं तक सभी स्कूल अलग व्यवस्था और शैली अपना रहे थे। परीक्षा, पढ़ाई, रिपोर्ट कार्ड भी स्कूलों के अपने-अपने होते थे। उसमें कोई मानकीकरण या बैंच मार्किंग नहीं होती थी। जब दसवीं में बोर्ड ले आए हैं तो इसकी तैयारी के फलस्वरूप छठी से आठवीं तक सिलेबस और पढ़ाई में एकरूपता रखनी पड़ेगी, इसीलिए यह सिस्टम लागू किया है। छात्र छठी में 60 प्रतिशत, सातवीं में 70 प्रतिशत और आठवीं में 80 प्रतिशत कोर्स पढ़ेगा, फाइनल एक्जाम में आएगा। फिर नौवीं में वर्ष भर का सिलेबस आएगा। नौवीं और दसवीं एक जैसी होगी। इस तरह का सिलेबस बनाया गया है। जो छात्रों की पढ़ाई के अनुकूल है।

मैं दुनिया के पढ़ाई सिस्टम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन, हमारे देश में पढ़ाई की गुणवत्ता का जो परम्परागत तरीका है हम उस पर चल रहे हैं। छात्रों को आगे परीक्षाएँ देना है। आईआईटी, कैट, स्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करना है। उसके अनुरूप नया बदलाव लागू किया गया है। बच्चों को उसी अनुसार तैयार करना पड़ेगा नहीं तो बच्चा आगे मिसफिट हो जाता है। पढ़ाई की नई व्यवस्था को हर किसी ने माना है, पसंद किया है। सबने इसे स्वीकार किया है। सब कह रहे हैं कि नए पैटर्न से बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे। जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी परीक्षा भी होनी चाहिए। अनुशासन भी होना चाहिए। तभी तो वह सीबीएसई स्कूल में फीस दे रहे हैं, तो वे अनुशासन, परीक्षा और पढ़ाई भी चाहते हैं। हमने इस व्यवस्था से जुड़े बहुत सारे लोगों से चर्चा की थी। जिसमें स्कूलों में प्रिंसिपल, टीचर्स, पैरेंट्स आदि से भी इस पर चर्चा हुई। छह-सात बार वर्कशॉप भी आयोजित हुई, जिसमें इन सबसे चर्चा हुई। उन लोगों ने जैसा कहा उसी के अनुसार नया सिस्टम तैयार किया है। कोई भी सर्कुलर हम खुद नहीं बनाते हैं। पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई है। कोई भी पैटर्न एकदम से नहीं बदलता है, उसके पीछे पूरी प्रोसेस होती है। एक-एक बदलाव करने में तीन से चार महीने लगे हैं।

इसी के साथ हमने सीबीएसई के सभी 18 हजार स्कूलों के लिए एक जैसा मार्कशीट सिस्टम

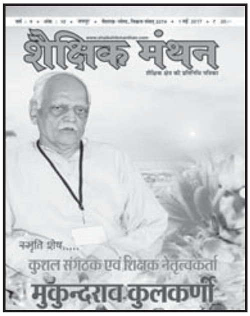

पढ़ाई का मतलब सिर्फ शैक्षणिक विकास नहीं है बल्कि इसका उद्‌देश्य तो विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास करना है। ऐसा विकास, जिसे हम सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं आँक सकते। नया पैटर्न क्यों लाया गया, यह तो सीबीएसई के अधिकारी ही बता सकते हैं। हो सकता है उनके पास अपने पक्ष में कुछ आँकड़े भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि हर विद्यार्थी के व्यक्तित्व के कई आयाम होते हैं और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो उनके हर आयाम का विकास करे। आठ साल पहले जब हम सीसीई (कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन) लाए थे तब सोच यही थी कि नई पीढ़ी का मूल्यांकन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि को-स्कॉलिस्टिक लर्निंग (जिंदगी में काम आने वाले कौशल, कार्य आधारित शिक्षा, ललित कलाएँ, रवैया और जीवन मूल्यों) के आधार पर किया जाए ताकि विषय ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट और व्यावहारिक उपयोगिता के साथ-साथ विद्यार्थियों की रुचियों को पहचाना जा सके, हम उन्हें आगे बढ़ा पाएँ।

शुरू किया है। यह एकरूपता की दिशा में बेहतर कदम है। 12वीं में भी मार्कशीट और ग्रेड सिस्टम होता है। उसी सिस्टम को हमने यहाँ शुरू किया है। सीसीई अब बीती हुई बात हो गई है। अब नया असेसमेंट सिस्टम शुरू हो गया है। बोर्ड परीक्षा गई है। शिक्षण का नया सिस्टम गया है, जो बच्चों को पढ़ाई के लिए अधिक प्रेरित करेगा।

पढ़ाई का मतलब सिर्फ शैक्षणिक विकास नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य तो विद्यार्थियों का सम्पूर्ण विकास करना है। ऐसा विकास, जिसे हम सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं आँक सकते। नया पैटर्न क्यों लाया गया, यह तो सीबीएसई के अधिकारी ही बता सकते हैं। हो सकता है उनके पास अपने पक्ष में कुछ आँकड़े भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि हर विद्यार्थी के व्यक्तित्व के कई आयाम होते हैं और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो उनके हर आयाम का विकास करे।

आठ साल पहले जब हम सीसीई (कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन) लाए थे तब सोच यही थी कि नई पीढ़ी का मूल्यांकन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, बल्कि को-स्कॉलिस्टिक लर्निंग (जिंदगी में काम आने वाले कौशल, कार्य आधारित शिक्षा, ललित कलाएँ, रवैया और जीवन मूल्यों) के आधार पर किया जाए ताकि विषय ही नहीं, उसके कॉन्सेप्ट और व्यावहारिक उपयोगिता के साथ-साथ विद्यार्थियों की रुचियों को पहचाना जा सके, हम उन्हें आगे बढ़ा पाएँ। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग (निष्पक्ष विश्लेषण मूल्यांकन की क्षमता) और गुणों का आँकलन कर जान सकें कि वे विपरीत हालातों में चुनौतियों का मुकाबला करने के कितने काबिल हैं। यह तो तय ही था कि इसे लागू करने में वक्त लगता लेकिन, यह जरूर है कि यह बदलाव आकार लेने लगा था। कुछ स्कूलों को सीसीई पैटर्न समझने में दिक्कतें आईं, सवाल भी उठाए गए। यह तक कहा जाता था कि विद्याथियों को अंग्रेजी में एप्लीकेशन भी लिखनी नहीं आती लेकिन, यह समस्या दृष्टिकोण की थी। अगर आपको विद्यार्थी कम अंक आने पर दुखी नहीं दिख रहे या परीक्षा से पहले तनाव में नहीं हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वे परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं। यह तो सकारात्मक पहलू है।

2008 से पहले सीबीएसई दो सर्टिफिकेट जारी करता था-एक एकेडमिक दूसरा को-स्कॉलिस्टिक यानी 2008 से पहले भी को-स्कॉलिस्टिक असेसमेंट होता था लेकिन, लोगों को इसकी अहमियत पता नहीं थी, इसलिए अभिभावक दूसरा सर्टिफिकेट लेने ही नहीं आते थे। देश के जिन स्कूलों में एक क्लास में ज्यादा छात्र होते थे, वहाँ शिक्षकों ने सीसीई पैटर्न को लागू करने में गंभीरता नहीं दिखाई। थर्ड पार्टी असेसमेंट की ही रिपोर्ट्स देख लीजिए-सीसीई पैटर्न की वजह से बोर्ड या जेईई मेन्स के रिजल्ट में कोई गिरावट नहीं आई। सीसीई का मकसद पढ़ाने के तरीकों को वक्त के मुताबिक बदलना था। पारम्परिक तरीकों से आगे बढ़कर लर्निंग बेस्ड तरीकों के प्रति रुचि पैदा करना था। हमने 11वीं के विद्यार्थियों पर सीसीई का असर जाँचने के लिए कई बार रैंडमली चैक किया तो पाया कि वे बेहतर सीख और समझ पा रहे थे। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि वे सेल्फ स्टडी की ओर बढ़ने लगे थे। माहौल ऐसा बन गया था, जहाँ शिक्षक सिर्फ उनके मददगार थे। ❑

(स्तंभ लेखक)

पुण्य स्मरण

कुशल संगठक एवं शिक्षक नेतृत्वकर्ता मा. मुकुन्दराव कुलकर्णी

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संस्थापक, लम्बे समय तक महासंघ के अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री रहे माननीय मुकुन्दराव कुलकर्णी का दिनांक 3 अप्रैल 2017 को पुणे में असामयिक देहावसान हो गया। माननीय मुकुन्दराव जी ने माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अपना शिक्षक जीवन प्रारम्भ किया, जहाँ लगभग एक दशक तक अध्यापन तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद् में कार्य प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् महाराष्ट्र विधान परिषद् के दो बार 1966-1978 सदस्य रहे। विधान परिषद् में शिक्षक क्षेत्र के सदस्य के नाते जीवन में सभी राजनीतिक दलों के लोगों से उनके मधुर संबंध रहे। यद्यपि उस समय वे विपरीत विचारधारा के सदस्य थे पर शासक दल के सभी सदस्यों सहित शिक्षा मंत्री भी उनकी बात बड़े ध्यान से सुनते थे तथा शिक्षकों की समस्याओं का सहज समाधान हो जाता था। उनका व्यवहार अत्यन्त मधुर था तथा वे अपनी बात तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते थे। वार्तालाप में तथ्य एवं तर्कों से वे सामने वाले को निरूत्तर कर देते थे।

शिक्षक एवं विधान परिषद के सदस्य रहते हुये उन्होंने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद् की ओर से अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ (AISTF) में काम करना प्रारम्भ किया। इस महासंघ के वे कई बार महामंत्री एवं अध्यक्ष रहे। परन्तु वहाँ काम करते हुये उनके मन को समाधान नहीं मिलता था। क्योंकि ये संगठन केवल शिक्षकों के आर्थिक हितों के लिये ही प्रयत्न एवं प्रयास करते थे। शिक्षा एवं राष्ट्र की समस्याओं के समाधान में भी शिक्षक संगठनों की कोई भूमिका होनी चाहिये, यह इन संगठनों में कोई मानने को तैयार नहीं था। जबकि कुलकर्णी जी का मानना था कि शिक्षक संगठन केवल शिक्षक हितों के लिये ही काम नहीं करते वरन शिक्षा, समाज व राष्ट्र हित के लिये भी प्रयास करें। जब वहाँ रहकर इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती दिखाई दी तो वहाँ रहते ही इनकी योजना एवं सोच में से भारतीय शिक्षण मंडल की स्थापना सातवें दशक में हुई, जिसके वे संस्थापक अध्यक्ष बने। शिक्षण मंडल की स्थापना, शिक्षा की रीति-नीति पर विचार करने के लक्ष्य से की गई थी, जिसमें शिक्षक हितों की पूर्ति का ध्यान रखकर शिक्षक संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ता भी शिक्षण मंडल के साथ जोड़े।

परन्तु ध्यान आया कि शिक्षक हितों की पूर्ति के लिये शिक्षण मंडल से काम संभव नहीं है। अत: अलग से एक पृथक संगठन की कल्पना करते हुये पहले अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ तथा नाम परिवर्तन कर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थापना की। माननीय कुलकर्णी जी इस संगठन के भी संस्थापक अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात् दीर्घावधि तक संगठन मंत्री के रूप में कार्य करते हुये राष्ट्रीय सोच से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं को शैक्षिक महासंघ के साथ जोड़ने हेतु संपूर्ण देश में निरन्तर प्रवास किया।

अन्य शिक्षक संगठनों के अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर शैक्षिक महासंघ में नवीन कल्पना दी, जहाँ 'पूर्व प्राथमिक से उच्च शिक्षा' तक के शिक्षक इसके सदस्य बन सकते हैं। अपने स्तर के अनुरूप अपनी समस्याओं और हितों पर चिन्तन करने हेतु पाँच संवर्गों की रचना की यथा- प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, महिला एवं शिक्षकेत्तर संवर्ग। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि जब अन्य लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने की सोचते भी नहीं थे तब भी शैक्षिक महासंघ में महिला संवर्ग की स्थापना कर महिला शिक्षकों में नेतृत्व विकास के लिये व्यवस्था की।

शैक्षिक महासंघ का ध्येय वाक्य 'राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक तथा शिक्षक के हित में समाज' यह उनकी सोच एवं दीर्घ अनुभव का परिचायक है। इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित किया कि वो शिक्षकों के हितों की चिन्ता करने के साथ-साथ राष्ट्र भाव के जागरण हेतु भी निरंतर प्रयासरत रहें। इस हेतु उन्होंने शैक्षिक महासंघ के कार्यक्रमों में कुछ स्थायी कार्यक्रम जोड़े। सर्वप्रथम अपने अतीत के प्रति गर्व एवं सम्मान के भाव जगाने के लिये नववर्ष (वर्ष प्रतिपदा) को उत्साह के साथ व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय किया। ताकि नववर्ष की वैज्ञानिकता एवं प्राचीनता न केवल शिक्षक समुदाय वरन् समाज में प्रचारित एवं स्थापित की जा सके। तत्पश्चात् न केवल शिक्षकों में वरन् समाज में दायित्व के जागरण हेतु दूसरा स्थायी कार्यक्रम कर्त्तव्य बोध दिवस के रूप में दिया। इनके अतिरिक्त समय-समय पर समसामयिक विषयों पर राष्ट्र जागरण की दृष्टि से स्वदेशी भावना जागरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण, शिक्षा का अधिकार, मातृभाषा में हो प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयों लेकर कार्यकर्ताओं की तद्नुरूप सोच बनाने तथा समाज को प्रेरित करने का काम किया। उनकी सोच व निरंतर आग्रह के कारण आज महासंघ शिक्षक सम्मान में वृद्धि एवं शिक्षक भाव जाग्रत करने के लिये गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

संगठन को स्थायित्व एवं सुदृढ़ आर्थिक आधार देने के लिये भी वे सतत् प्रयत्नशील रहते थे। इसी सोच के चलते पुणे में भूमि खरीद कर शिक्षण मंडल एवं शैक्षिक महासंघ के कार्यालय की योजना बनाई तथा उनके 75 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उनके अभिनंदन को निमित्त बनाकर देश भर से धन संग्रह हेतु अनुमति प्रदान की। कितनी स्पष्ट सोच थी कि उन्होंने

कहा कि 'सम्मान मेरा पर धन शैक्षिक महासंघ का होगा'। आज का शैक्षिक महासंघ का दिल्ली कार्यालय उनके अभिनंदन हेतु संग्रहित धनराशि से ही खरीदा गया है। इस प्रकार उन्होंने संगठन को पुष्ट करने व संसाधनों से युक्त करने की अनूठी योजना का सम्मान के निमित्त सूत्रपात किया।

जीवन के उत्तरार्द्ध में उन्हें सुनने व चलने में कठिनाई होने पर दायित्वमुक्त होने के बावजूद शैक्षिक महासंघ के उत्तरोत्तर विकास एवं वृद्धि के लिये सदैव चिंतित रहते थे। आज के कार्यकर्ताओं को टोली में से बहुतांश कार्यकर्ताओं को जोड़ने, विकसित करने व ध्येय समर्पित बनाने में माननीय कुलकर्णी जी की महत्ती भूमिका रही है।

मा. मुकुन्दराव कुलकर्णी जी धुले में अपने वकील पिता के कठोर अनुशासन में पले बढ़े, उन्हीं के आग्रह से अखाड़े में जाया करते थे। पिताजी जब प.पू. डॉक्टर जी के सम्पर्क में आए और संघचालक का दायित्वनिर्वहन किया, तब संघ के उन्हीं संस्कारों को लेकर मा. कुलकर्णी जी बाल्यावस्था से स्वयंसेवक बने। अध्ययन-अध्यापन के लिए वे पुणे में आ गये। यहीं संघ कार्य में कार्यकर्ता के नाते कार्य करते हुए जीवन का सर्वस्व समर्पित कर पंच महाभूतों में लीन हो गये।

मा. मुकुन्दराव कुलकर्णी जी को श्रद्धाञ्जलि

माननीय मुकुन्दराव कुलकर्णी जी को भारतीय शिक्षण मंडल तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की स्थापना का श्रेय है। दोनों संगठनों के वे संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। शैक्षिक महासंघ का ध्येय वाक्य- 'राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक तथा शिक्षक के हित में समाज' कुलकर्णी जी की शैक्षिक महासंघ से राष्ट्र व समाज की अपेक्षा को स्पष्ट करता है। पचास के दशक में स्थापित शिक्षक संगठन, AIFTD, AIFEA आदि का उनका अनुभव तथा बाद में बने AIPTF, AISTF एवं AIFUCTO की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखकर उन्होंने शैक्षिक महासंघ की स्थापना की। जो एक होते हुये भी विभिन्न संवर्गों के वर्ग हितों की चिन्ता कर सकता है तथा अलग-अलग संवर्गों के हितों के लिये की गई रचना भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। आंदोलन का निर्णय कोई एक संवर्ग नहीं कर सकता वरन् सभी का सामूहिक निर्णय होगा। इस प्रकार अलग-अलग होते हुये भी हम एक ही हैं तथा अलग-अलग वर्ग हितों की चिन्ता करने के लिये स्वतंत्र होने के कारण अलग भी हैं। यह अनूठी कल्पना उनके व्यापक अनुभवों के कारण बनी।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ (AISTF) में कभी महामंत्री और कभी अध्यक्ष रहते हुये भी वे वहाँ समरस नहीं हो सके, क्योंकि उस संगठन में राष्ट्रीय सोच को कोई स्थान नहीं था। शिक्षक संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय सोच व विचार के प्रसारण हेतु कुलकर्णी जी ने शैक्षिक महासंघ की स्थापना की थी। सामान्यत: किसी संगठन में वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले को पद नहीं मिलता है तो वह अलग संगठन बना लेता है और बाद में पद मिलने पर यह कहते हुये वापस भी आ जाता है कि 'सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ गया है। परन्तु वे सुबह के भूले हुये नहीं थे अत: शाम को घर वापिस आने की बात ही नहीं है।' लक्ष्य स्पष्ट था कि शिक्षक संगठन भी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में सहायक एवं सहभागी बने।

राष्ट्रभाव के जागरण के लिये समाज को अपने अतीत का ध्यान होना चाहिये, इस दृष्टि से कालगणना का भान कराने के लिये नववर्ष जो वर्ष प्रतिपदा, गुडी पड़वा, युगाब्द आदि नाम से देश में मनाया जाता है उसे उत्साहपूर्वक व्यापक स्तर पर शैक्षिक

श्रद्धाञ्जलि

माननीय मुकुन्दराव कुलकर्णी जी पाँच दशक से अधिक समय तक शिक्षा, शिक्षक एवं समाज की सेवा में रत रहे। आपकी प्रभाव क्षमता, नेतृत्त्व क्षमता, कार्य क्षमता एवं प्रशासनिक क्षमता इतनी अद्भुत् थी कि विरोधियों को भी उनकी सलाह को स्वीकार करना पड़ता था। आपने शिक्षक संगठनों की एक नवीन परिभाषा गढी जिसमें शिक्षक संगठनों को शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ शिक्षा एवं समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करना होगा। इसी कारण अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ को दुनिया के सभी शिक्षक संगठनों से अलग एवं अनोखा माना जाता है। सही मायने में आदरणीय कुलकर्णी जी एक तपस्वी शिक्षक संत थे जो जीवनपर्यन्त शिक्षा एवं शिक्षक के लिए कार्य करते रहे। प्रखर राष्ट्रवादी, ध्येयनिष्ठ महासंघ के संस्थापक माननीय कुलकर्णी जी के असामयिक निधन पर हम सभी शोकाकुल हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं तथा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें। ईश्वर शोकाकुल परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने का सामर्थ्य प्रदान करें तथा हम सभी को उनके बताये मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करें।

– जगदीश प्रसाद सिंघल, राष्ट्रीय महामंत्री

महासंघ में मनाने का निर्णय किया गया। जिसके सुफल दिखने भी लगे हैं। इसी प्रकार देश में क्षीण हो रहे कर्त्तव्य भाव को जगाने के लिये कर्त्तव्य बोध दिवस की योजना की गई। ये दोनों ही स्थाई कार्यक्रम आज संगठन में स्थापित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त समसामयिक समस्याओं यथा–इतिहास का विकृतिकरण, मातृभाषा में हो प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा के अधिकार का कानून जैसे अनेक विषयों पर व्यापक जनजागरण के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

कुलकर्णी जी ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक निरंतर प्रवास व प्रयास कर व्यापक संपर्क स्थापित किया तथा उनमें से चयन कर कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। आज की टोली सहित हजारों कार्यकर्ताओं के निर्माण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कार्य के लिये प्रयास के महत्त्व को स्वीकार कर वे सदैव चलते रहे। इस व्यापक प्रवास के कारण परिवार की उपेक्षा हुई है यह परिवारजनों ने अनुभव किया है व व्यक्त भी किया है। इसका स्पष्ट संदेश है कि संगठन के विस्तार एवं विकास के लिये व्यापक संपर्क एवं प्रवास आवश्यक है।

शिक्षक समस्याओं के समाधान के लिये धरने, प्रदर्शन, मोर्चे, विचार विमर्श आदि सभी प्रकार के कार्यक्रमों को भी उन्होंने अपनाया था तथा अनेक समस्याओं का समाधान भी प्राप्त किया था। कार्यकर्ता तथ्य तर्क के साथ अपने विषय रखें तभी सहज समाधान मिल सकता है। इन सबके प्रशिक्षण के लिये अभ्यास वर्गों के आयोजन पर उनका विशेष आग्रह रहता था।

शैक्षिक महासंघ की स्थापना के समय महिला नेतृत्व की व्यापक कल्पना जब अन्य कोई नहीं कर रहा था तब अपने इस संगठन में महिला नेतृत्व खड़ा करने तथा उनकी महिला के नाते होने वाली समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान की व्यवस्था खड़ी करने के लिये 'महिला संवर्ग' का निर्माण किया गया। इस व्यवस्था के फलस्वरूप देश में अनेक स्थानों पर सशक्त महिला नेतृत्व खड़ा हुआ है।

माननीय कुलकर्णी जी की व्यापक सोच, निरन्तर प्रवास के आग्रह, कार्यकर्ता के प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु अभ्यास वर्गों व कार्यशालाओं के आयोजन आदि के माध्यम से हम अपने संगठन का विकास एवं विस्तार करते हुये ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली ज्ञापित कर सकते हैं।

दो बार विधान परिषद् का सदस्य रहते हुये भी इस व्यवस्था का लाभ शिक्षकों एवं शिक्षक संगठन की समस्याओं के समाधान के लिये किया। किसी प्रकार का लोभ, लालच, भय, आकर्षण उनको छू भी नहीं सका। इतनी दीर्घावधि व विपरीत स्वास्थ्य के बाद भी इसी कार्य में अहर्निश लगे रहे। शिक्षक संगठनों के इतिहास में ऐसे कम ही उदाहरण मिल सकेंगे जहाँ कोई व्यक्ति लगातार पाँच दशक तक निरन्तर सक्रिय रहा हो। उनका यह सुदीर्घ अनुभव भी हमको सदैव कार्यशील रहने की प्रेरणा प्रदान करता है।

– डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष

जम्मू कश्मीर प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग सम्पन्न

प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग एवं प्रदेश कार्यकारिणी बैठक ऑल जम्मू कश्मीर एण्ड लद्दाख टीचर्स फेडरेशन जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध है का दो दिवसीय प्रदेश कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग एवं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 24 अप्रैल 2017 को सम्पन्न हुई। जिसमें अ.भा.रा. शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेन्द्र कपूर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जगदीश चौहान एवं राष्ट्रीय आन्तरिक अंकेक्षक श्री पवन मिश्रा पूरे समय तक उपस्थित रहे। अभ्यास वर्ग एवं बैठक में जम्मू सम्भाग के 10 जिलों के जिला एवं प्रान्त स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। अभ्यास वर्ग में संगठन का विचार, कार्यकर्ता प्रवास का महत्त्व सदस्यता, वार्षिक समीक्षा एवं आगामी योजना आदि विषयों पर केन्द्रीय पदाधिकारियों द्वारा विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

अन्त में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जम्मू कश्मीर प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें श्री देवराज ठाकुर अध्यक्ष, रतन शर्मा प्रदेश महामन्त्री, महेश्वर प्रसाद, दर्शन भारती और प्रदीप कुमार तीन उपाध्यक्ष, कुसुम कुमारी महिला उपाध्यक्ष, शिवदेव सिंह, मन्जीत सिंह और नीरज शर्मा प्रदेश मन्त्री, रविन्द्र वर्मा कोषाध्यक्ष, राधाकृष्ण मीडिया प्रभारी, मोहन सिंह आन्तरिक अंकेक्षक और कुलदीप सिंह को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया।

नई कार्यकारिणी के साथ आगामी योजना भी बनाई गई। जिसमें – प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक साल में तीन बार, अप्रैल, अगस्त और दिसम्बर में होगी, 2. सदस्यता के साथ अभ्यास वर्ग वर्ष में दो बार समर जोन का मई में और विन्टर जोन का 15 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक किया जायेगा। 3. प्रदेश का अभ्यास वर्ग प्रति वर्ष गर्मी की छुट्टियों में रहेगा। 4. प्रान्त स्तर का एक विशाल कार्यक्रम तीन वर्ष में एक बार होगा।

बैठक के अन्तिम एवं समापन सत्र में राष्ट्रीय संगठन मन्त्री श्री महेन्द्र कपूर ने नव नियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी को बधाई देते हुए भविष्य में शैक्षिक महासंघ का प्रदेश में कार्य तीव्र गति से आगे बढ़े, अपेक्षा के साथ समापन किया।

गतिविधि

'सामाजिक समरसता' पर लखनऊ में संगोष्ठी सम्पन्न

सशक्त राष्ट्र के लिए समरस-सशक्त समाज की आवश्यकता है। डॉ. अम्बेडकर का पूरा संघर्ष समाज और राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए रहा। सामाजिक समरसता एवं शिक्षा में समानता के प्रबल पक्षधर बाबा साहब ने ऐसे स्वाभिमानी राष्ट्र की संकल्पना को यथार्थ रूप दिया जिसमें समाज के सभी वर्गों, धर्मों व जातियों को समान अधिकार व अवसर प्राप्त हो।

उक्त बातें राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश एवं व्यापार प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 22 अप्रेल 2017 को मालवीय सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी डॉ. आंबेडकर एवं सामाजिक समरसता' पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, माननीय रमापति शास्त्री जी ने कही। उन्होंने आगे कहा की डॉ. अम्बेडकर एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं आर्थिक असमानता न हो। उनका दृढ़ विश्वास था कि जाति व वर्ण व्यवस्था का उन्मूलन किये बिना सामाजिक व आर्थिक समानता संभव नहीं है। समानता के बिना देश व समाज का विकास संभव नहीं है।

मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री ओम पाल सिंह ने कहा कि अम्बेडकर का दर्शन समाज को गतिमान बनाए रखने का है। व्यक्ति की महानता उसके कर्म से सुनिश्चित होती है न कि जन्म से। वंचितों को सशक्त करने और उन्हें शिक्षित करने का उनका अभियान एक तरह से हिंदु समाज और राष्ट्र को सशक्त करने का अभियान था। सदियों से अभिशप्त, वंचित-दलित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करने व अस्पृश्यों और दलितों के उद्धार के लिए दलितों में से ही नेतृत्व उभारने का मार्ग डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने दिखाया। डॉ. अम्बेडकर के प्रयासों का ही फल है कि शिक्षा के प्रसार में जातिगत-भौगोलिक व आर्थिक असमानताएँ बाधक न बन सकीं, इसकी व्यवस्था संविधान व नीति निर्देशक तत्वों में की गई। शिक्षा अधिकार का क्रियान्वयन भी इन्हीं का परिणाम है। उनके अनुसार शिक्षा का बड़ा उद्देश्य लोगों में नैतिकता व जनकल्याण की भावना विकसित करना होना चाहिए। पीढियों को तराशने का कार्य करने वाले शिक्षकों का कर्तव्य है कि बाबा साहब के शैक्षिक व सामाजिक विचारों को समाज में स्थापित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभायें जिससे समरस-सशक्त एवं समृद्ध भारत का निर्माण संभव हो सके।

अध्यक्षता करते हुए विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के संरक्षक पद्मश्री ब्रह्मदेव शर्मा भाई जी ने कहा की भारतीय संस्कृति को समृद्ध और श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ा योगदान वंचित समाज के लोगों का है। डॉ अम्बेडकर का सपना था कि समतामूलक समाज हो, शोषण-मुक्त समाज हो। उनके समूचे जीवन और चिंतन के केंद्र में यही एक सपना की जातिविहीन, वर्गविहीन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषमताओं से मुक्त समाज। अम्बेडकर इस देश के संघर्षशील और परिवर्तनकारी समूहों के हर महत्त्वपूर्ण सवाल पर प्रासंगिक है इसी कारण वह विकास के लिए संघर्ष के प्रेरणास्रोत भी बन गए हैं।

विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार सिंह ने कहा की बाबा साहब का मत था कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण कर सकती है। संस्कारयुक्त शिक्षा और सम्पूर्ण पीढ़ी को संस्कारित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की ही है, उन्होंने पाठ्यक्रमों का स्वरूप, विद्यार्थियों के दायित्व, शिक्षकों की पात्रता, शिक्षण संस्थाओं का उत्तरदायित्व, सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था आदि विषयों पर चिन्तन कर समयानुकुल अनिवार्यता पर बल दिया। शिक्षा से ही व्यक्ति-समाज व राष्ट्र का समग्र विकास हो सकता है। उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति विकसित करने पर बल दिया जो बौद्धिक विकास के साथ चरित्र निर्माण कर विद्यार्थी को सुयोग्य नागरिक बनाये।

विशिष्ट अतिथि बैसवारा विकास समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश सिंह ने कहा कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था व नीति में जो भी कमियाँ है, उनका निवारण बाबा साहब के विचारों में खोजा जा सकता है और सामाजिक और आर्थिक अवसरों की समानता वाले समाज की रचना की जा सकती है।

संगोष्ठी की विषय प्रस्तावना रखते हुए व्यापार प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष संजय मेधावी ने कहा कि अम्बेडकर चाहते थे कि देश के हर बच्चे को एक समान, अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिले, चाहे व किसी भी जाति, पंथ या वर्ग का क्यों न हो। आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही अम्बेडकर ने रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की वकालत की थी।

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश लखनऊ विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष प्रो. सोमेश कुमार शुक्ल ने संगठन की प्रस्तावना रखते हुए कहा की शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वैचारिक अधिष्ठान की संकल्पना लेकर यह संगठन कार्य करता है। जिसका ध्येय है देश के लिए शिक्षा, शिक्षा के लिए शिक्षक और शिक्षक के लिए समाज खड़ा हो इसके लिए महासंघ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।

इस अवसर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के संस्थापक, लम्बे समय तक महासंघ के अध्यक्ष एवं संगठन मंत्री रहे माननीय मुकुंद राव कुलकर्णी की स्मृति में दो मिनट का शोक रख कर श्रद्धांजली अर्पित की गयी।

संगोष्ठी का सञ्चालन संयोजक अम्बरीष सिंह ने किया। संगोष्ठी विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक-छात्र और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहें ।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर राज्य स्तरीय कार्यशाला सोलन हि.प्र. में सम्पन्न

विद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विषय पर हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ द्वारा प्रथम राज्यस्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला सोलन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रुगडा के सहयोग से आस्था शिक्षा महाविद्यालय, कुनिहार में किया गया। इसका शुभारम्भ सरस्वती वन्दना से किया गया।

प्रथम सत्र में डॉ. हरबंस राणा द्वारा 'गुणवत्ता शिक्षण और अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ' विषय पर गुणवत्ता के 6 मॉडल की प्रासंगिकता देते हुए कहा कि Assessment, Autonomy, Accountability, Attention to Teachers, Attention to early child Development और Attention to Culture भी गुणवत्ता में सहयोगी हो सकते हैं। बच्चे के मन को पढ़ कर हम उसमें पाठ्यक्रम के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं. सभी बच्चों तक कैसे पहुँचे, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इसके लिए समूह योजना के द्वारा बच्चों को दूसरे पढाई में अच्छे बच्चों के बराबर लाया जा सकता है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए शुकदेव शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षकों के द्वारा शिक्षण-अधिगम को कैसे प्रभावी बनाया जाये, यह साझा करने की आवश्यकता है।

दूसरे सत्र में प्रो. रोमेश चन्द कौंडल ने 'गुणवत्ता की समझ और कक्षा-कक्ष में प्रभावशाली अधिगम' विषय पर विचार रखते हुए कहा कि अध्यापक को अपने शिक्षण में गुणवत्ता लाने हेतु सबसे पहले बच्चे को समझना होगा। अपने शिक्षण में नए तरीके अपनाकर अध्यापक कक्षा-कक्ष में नीरसता को खत्म करना है, उसी से हम बच्चे के मन को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। गुणवत्ता शिक्षण विभिन्न पक्षों पर निर्भर करता है जिनमें विद्यार्थी, अध्यापक, साथी एवं मित्र और माता-पिता हैं. परन्तु मुख्य तौर पर यह व्यक्तिगत भी है। सत्र की अध्यक्षता करते हुए जगवीर चन्देल ने प्रो. कौंडल द्वारा बताई गई गुणवत्ता शिक्षण की विधियों को उचित ठहराते हुए सभी अध्यापकों से इनको कक्षा-कक्ष में अपनाने की बात कही।

तीसरे सत्र में रा.व.मा.वि. जेजवीं के जीव विज्ञान प्रवक्ता सुरेश कपिल ने विद्यार्थी के बौद्धिक विकास में गुणवत्ता शिक्षण की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानन्द, डॉ. राधाकृष्णन, चाणक्य और विदुर जैसे विद्वानों द्वारा बताए गए बच्चे के बौद्धिक विकास की साधारण गतिविधियों को अपनाने की बात कही, जैसे हम विद्यालय में लिखे प्रेरक वाक्यों को रोज पढ़ते हैं लेकिन उनको आत्मसात नहीं करते। संस्कारों के माध्यम से व्यक्ति को गुणवान बनाया जा सकता है'। सत्र के अध्यक्ष विनोद सूद ने अपने उदबोधन में बताया कि संस्कार व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाते हैं। विद्यालयों में होने वाली प्रात: कालीन सभा में करवाई जाने वाली गतिविधियाँ व्यक्ति में उन गुणों का विकास करती हैं जो उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है।

कार्यशाला के अध्यक्ष रजनीश चौधरी ने तीनों सत्रों के विषयों को विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षण को उपयोगी बताया तथा स्कूलों में अपनाने की अपील की। आभार श्री कश्मीर सिंह के द्वारा किया गया।

'सवा लाख से एक लड़ाऊँ' पुस्तक का हुआ विमोचन

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आयोजित 27 अप्रैल 2017 को दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय के सभागार में 'सवा लाख से एक लडाऊँ' नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। प्रख्यात लेखक एवं वक्ता श्री हनुमान सिंह राठौड़, अनुसंधान अधिकारी, अजमेर, ने गुरु गोबिंद सिंघ जी का जीवन परिचय दिया और उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के इतिहास से सभी को अवगत कराया। गुरु गोबिंद सिंघ जी ने मात्र 42 सिखों के साथ चमकौर (1705) की दूसरी लड़ाई में 10 लाख मुगल सेना के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध के बाद उन्होंने यह नारा दिया - 'सवा लाख से एक लड़ाऊँ'। हनुमान सिंह राठौड़ जी ने गुरु गोबिंद सिंघ जी के संदेश का सार बताया। श्री गुरु ग्रन्थ साहिब का संकलन तथा इसकी घोषणा के बारे में, खालसा पंथ की स्थापना आदि विषयों पर पुस्तक में गहराई से चर्चा है। अपने उत्तराधिकारी के रूप में बाबा बंदा बैरागी को सिख बनाने तथा उन्हें खालसा पंथ का सरदार बनाने के बारे में भी विस्तार से बताया गया। गुरु गोबिंद सिंघ जी लोगों के चयन में सर्वश्रेष्ठ थे, महान संयोजक तथा आध्यात्मिक गुरु थे। पुस्तक में केवल तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं है, अपितु यह गुरु गोबिंद सिंघ जी के जीवन और कर्मक्षेत्र पर एक अच्छा शोध दस्तावेज है। प्रो. एम. जगदीश कुमार, कुलपति, जेएनयू मुख्य अतिथि थे ।

पुस्तक विमोचन के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर, डीन तथा प्राचार्य उपस्थित रहे। अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अ.भा.रा.शै.महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विमल प्रसाद अग्रवाल ने की। इस अवसर पर शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शैक्षिक महासंघ (उच्च शिक्षा संवर्ग) की दिल्ली इकाई, दिल्ली अध्यापक परिषद् और नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (एनडीटीफ) के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

बंगीय नव उन्मेष प्रा. शि. सं. की कोलकाता में संगोष्ठी सम्पन्न

बंगीय नव उन्मेष प्राथमिक शिक्षक संघ, कोलकाता महानगर द्वारा दक्षिण कोलकाता के आशुतोष मेमोरियल हाल में 'बंगाल में धार्मिक जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन व शिक्षा क्षेत्र में इसका प्रभाव'– विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 28 अप्रैल को मुख्य वक्ता टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के डीन डॉ. स्वरूप प्रसाद घोष व मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दक्षिण बंगाल प्रान्त कार्यवाह डॉ. जिष्णु बासु। संस्कार भारती राष्ट्रगीत तथा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ।

श्रीमती गार्गी मित्रा के साथ स्वागत भाषण में बंगीय नव उन्मेष प्राथमिक शिक्षक संघ के पश्चिम बंगाल राज्य सचिव कानुप्रिय दास ने वर्तमान सरकार का मुस्लिम वोटबैंक पॉलिटिक्स के कारण राज्य के बिगड़ती हुई शिक्षा माहौल को व्यक्त किया। डॉ. जिष्णु बासु ने अपना वक्तव्य में बंगाल के सरकारी पाठ्यपुस्तकों में बंगला के बदले में अरबी शब्द प्रयोग करने का कड़ी आलोचना की। उन्होंने पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की करुण स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा के हिंदुओं की जनसंख्या घट जाने से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की स्थिति विकट है। ज्यादातर सरकारी विद्यालयों में infra-structure ख़राब होने के कारन माँ, बाप अपने बच्चों को वहाँ भेजना नहीं चाहते। डॉ. स्वरूप प्रसाद घोष ने बंगाल में हिंदुओं की घटती जनसंख्या के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बुद्धिजीवी अपने समाज के हित के बारे में नहीं सोचते। उच्च शिक्षित हिन्दू अपने देश के लिए समर्पित नहीं है। उनका ध्यान यूरोप या अमेरिका में स्थायी रूप में जाने पर है। योगेश चंद्र कालेज के अध्यक्ष डॉ. पंकज राय ने पश्चिम बंगाल सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति की निंदा की। अध्यापक देबाशीष चौधरी ने भी अपना मत रखा। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉ. निर्मलेंदु चक्रवर्ती ने अध्ययीय उद्बोधन में कहा कि मुसलमानों के मन्तव्य को समझने के लिए कुरान पढ़ने की जरूरत बताई। प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य सभापति सोमेन दास ने धन्यवाद व्यक्त किया। राष्ट्रगीत वंदेमातरम् के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ।

म.प्र. शिक्षक संघ की प्रान्तीय बैठक भोपाल में सम्पन्न

म.प्र. शिक्षक संघ की प्रान्तीय बैठक का आयोजन शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख रूप से 10 मई 2017 तक होने वाले प्रान्तीय निर्वाचन के कार्यक्रम की तिथि घोषित की गई। बैठक में वर्ष 2016-17 में होने वाली सदस्यता का लेखा-जोखा लिया गया। 10 मई को निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन करने का निर्णय लिया गया व प्रत्येक जिले से प्रान्तीय परिषद के सदस्यों की सूची जमा कराई गई।

प्रान्तीय बैठक में शिक्षा छात्र एवं शिक्षक हित में अनेक ज्वलंत माँगों को बैठक में रखा। सहायक शिक्षकों की एक मुश्त शिक्षक पद पर पदोन्नत करने व प्राचार्य, व्याख्याताओं की तरह शिक्षकों को भी समयमान वेतनमान देने की माँग को रखा गया। बैठक में उपस्थित 51 जिलों के प्रतिनिधियों के समक्ष म.प्र. में शिक्षक हित और सामाजिक सरोकार को लेकर चलाए जा रहे प्रकल्पों व नवाचारों की जानकारी दी गई। प्रान्ताध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में सहायक शिक्षकों को 15 दिवस में शिक्षक पद पर पदोन्नत होने की बात कही। उन्होंने कहा समयमान वेतनमान की माँग समाधान और सहायक शिक्षकों की पदोन्नति की माँग अंतिम चरण में है और वह आगामी 15 दिवस में पूर्ण हो जाएगी इसके लिए मुख्यमंत्री एवं शिक्षामंत्री द्वारा चर्चा के दौरान आश्वासन दिया।

केकड़ी इकाई ने सामाजिक समरसता दिवस मनाया

बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) केकड़ी उपशाखा के द्वारा आयोजित अम्बेडकर जयन्ती समारोह के मुख्य अतिथि प्रो. सांवर लाल जाट, सांसद एवं किसान आयोग के अध्यक्ष ने शिक्षकों को सम्बोधित करते हुये कहा कि वर्तमान में देश में जाति प्रथा सामाजिक समरसता के मनोभावों को अपनाने की महती आवश्यकता है। प्रो. जाट ने वर्षों पूर्व जाति छुआ-छूत के दंश से व्याप्त समाज की दुर्दशा से निकलने का रास्ता भाईचारे से जीवनयापन करना बताया। मुख्य वक्ता डॉ. नारायण लाल गुप्ता महामंत्री रुक्टा (राष्ट्रीय) ने बाबा साहब के समय दलितों के साथ एक जन, एक मन, एक राष्ट्र की राह पर समाज के सभी वर्ग को संबोधित किया। इस अवसर पर टोंक, सवाईमाधोपुर सांसद सुखवीर जोनपुरिया ने भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान की पालना सुनिश्चित हो इस नाते कहा कि देश के नागरिकों को समाज में व्याप्त छुआछूत दलित व्यवहार जैसी बुराइयों का त्याग करना होगा। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुये केकड़ी विधायक एवं संसदीय सचिव शत्रुघन गौतम ने दृढ़ता से विचार व्यक्त करते हुये कहा कि आज का युवा बदल रहा है, आवश्यकता है कि हम पुरानी प्रचलित विचारधाराओं को त्याग कर सभी मतभेद भुलाकर आपस में भाईचारे का व्यवहार करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बजरंग प्रसाद मजेजी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान निर्माण एवं उनके वेदों से प्रेरित विचारों को बताते हुये कहा कि व्यक्ति जन्म से शुद्ध माना जाय यह ठीक नहीं है। देश को आवश्यकता है कि समभाव से समान नागरिकता के नियम का पालन कर समाज में व्याप्त ऊँच-नीच मिटाकर दलितों के प्रति सद्भाव का वातावरण बनायें। उपशाखा अध्यक्ष कैलाश जैन ने अतिथियों का स्वागत किया। संचालन बिरदी चन्द वैष्णव ने किया, इस अवसर पर केकड़ी क्षेत्र के इस सत्र में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अतिथियों के द्वारा सम्मानित भी किया गया।

पेंशन पर अपील दायर के निर्देश, NDTF ने दिया खिलाफ में ज्ञापन

माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा विश्वविद्यालय के 1 जनवरी 1986 तक नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों को CPF व पेंशन पर दिए गये सकारात्मक व ऐतिहासिक फैसले पर मंत्रालय की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय को इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाला निर्देश सरासर अमानवीय व प्रताड़ित करने वाला निर्देश है।

करीब दो दशकों तक अस्पष्ट प्रक्रिया में उलझी इस लंबी लड़ाई के बाद आए निर्णय से हजारों शिक्षक व कर्मचारियों को जागी एक आशा पर यह एक बड़ा कुठाराघात है।

नियमों के सही क्रियान्वयन व परिस्थितियों के जंजाल में उलझे इस मसले से रिटायर्ड शिक्षक व कर्मचारियों की परेशानियों को सरकार को समझना ही होगा।

सरकार व मंत्रालय को समझना होगा कि इस निर्देश से न केवल 1 जनवरी 1986 तक नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों को पेंशन से वंचित करेगा बल्कि 1988 से 1998 के दिए समय में CPF से GPF में जाने वाले शिक्षक व कर्मचारियों की पेंशन भी छीन लेगा।

ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2014 में भाजपा सरकार के अस्तित्व मे आने पर व अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का रास्ता चुनने के बाद अकारण सैंकड़ों शिक्षक व कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के बिना जीने के लिए मजबूर हैं। जबकि उन्हीं के अन्य समकक्ष सरकारी साथियों को पेंशन की सुविधा मिल रही है। ऐसे में सैकड़ों शिक्षक व कर्मचारी आज बिना CPF और बिना पेंशन के बेहद मुश्किल परिस्थितियों में अपना पोस्ट रिटायरमेंट जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय व केन्द्र सरकार दोनों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी पूरी जिंदगी विश्वविद्यालय में सेवाएँ प्रदान करने के बाद आज ये शिक्षक व कर्मचारी क्यों पाई पाई का मोहताज बना दिए गये हैं?

MHRD व वित्त मंत्रालय की साझा जिम्मेदारी है कि इन शिक्षक व कर्मचारियों को न्याय सम्मत अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करें और उनकी परेशानी व पीड़ा को बढ़ाने वाले निर्देश भेजने वाले शरारती ब्यूरोक्रेट्स पर सख्त रहें।

NDTF सरकार व विश्वविद्यालय से अपील करता है कि हमारे वरिष्ठ शिक्षक व कर्मचारियों के हितों में इस निर्देश को वापस ले और लागू करने की कोई कोशिश न करें, व जल्दी से जल्दी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच द्वारा विश्वविद्यालय के 1 जनवरी 1986 तक नियुक्त शिक्षक व कर्मचारियों को CPF व पेंशन पर दिए गये सकारात्मक व ऐतिहासिक फैसले को लागू करने की दिशा में फैसला लें। NDTF हमेशा से इस विषय पूरी तरह से संबद्ध साथियों के पक्ष से अवगत कराता रहा है और कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार की ओर से शिक्षक व कर्मचारियों की पेंशन रोकने या पेशन से वंचित करने के किसी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्याशित कदम का विरोध करता है।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि मोदी सरकार की घोषित नीति है कि वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में कोर्ट व न्यायालयों से आए फैसलों पर किसी भी स्तर पर कोई भी पुनर्याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए। विक्षिप्त मानसिकता वाले ब्यूरोक्रेट्स ये जान लें कि सरकार ऐसे शरारती निर्देशों का संज्ञान लेगी तो वे भी मुश्किल में पड़ेंगे।

NDTF दिल्ली विश्वविद्यालय को पेंशन पर कोर्ट इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने वाला निर्देश का जोरदार विरोध करते हुए इसे ठुकराने की माँग करता है और विश्वविद्यालय को अपने विवेक से वरिष्ठ शिक्षकों व कर्मचारियों को कोर्ट से मिले फैसले को यथाशीघ्र लागू करने की दिशा में फैसला करने की माँग करता है।

मण्डोर इकाई द्वारा सामाजिक समरसता कार्यक्रम

संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय), उपशाखा मण्डोर द्वारा सामाजिक समरसता समारोह पिलाक बालाजी प्रांगण में आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि अति. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अशोक विश्नोई, प्रमुख वक्ता मोहन सिंह भाटी एवं विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर लाल काला, सभाध्यक्ष त्रिलोक राम नायल एवं रामजीवन पूर्व बीईईओ थे।

मुख्य अतिथि अशोक विश्नोई ने भारत रत्न बाबा साहब के सामाजिक समरसता में दिये गये योगदानों का उल्लेख करते हुए आपसी सामंजस्य एवं सहयोग से समाज के विकास का आह्वान किया। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण लाल काला ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर, सामाजिक समरसता का सन्देश दिया। सभाध्यक्ष त्रिलोकराम नायल ने वैचारिक समरसता के आधार पर सभी धर्म एवं वर्ग को एक साथ रखते हुए सामाजिक एकता बनाये रखने का सन्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख वक्ता मोहन सिंह भाटी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन को व्यक्त करते हुए संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपशाखा के प्रमुख शिक्षक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कृपाल सिंह चारण ने किया।

नरसिंहपुर (म.प्र.) में डॉ. अम्बेडकर पर संगोष्ठी सम्पन्न

भारतीय दर्शन में वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य-मनुष्य में भेद नहीं है बल्कि वह उसका परिजन है, स्वजन है। स्वाभाविक है स्वजनों में प्रेम होगा, सद्भाव होगा। ऊँच-नीच, दलित-शोषित जैसी कोई बात हमारे यहाँ नहीं थी, किन्तु विदेशी आक्रांताओं ने जो मनुष्य-मनुष्य के बीच खाई पैदा की उसमें ऊँच-नीच, दलित शोषकों की अमानवीय वृत्ति ने बड़ा स्वरूप धारण कर लिया, जिससे हमारा सामाजिक विकास अवरुद्ध हो गया। यह उद्गार आनन्द नेमा ने मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, नरसिंहपुर में भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में 'समरसता की प्रासंगिकता और शिक्षकों की भूमिका' विषय पर व्यक्त किये। उन्होंने शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करते हुये कहा कि इस कुप्रथा में शिक्षक बच्चों के साथ अनेक गतिविधियाँ आयोजित कर सभी वर्ग जाति व धर्म के लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश करें। संगोष्ठी में शिक्षक संघ के जिला सचिव आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव ने अम्बेडकर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुये उन्हें वर्तमान भारत की सामाजिक समृद्धता का मसीहा निरूपित किया। संगोष्ठी में परवेज अख्तर खान ने डॉ. अम्बेडकर से जुड़े संस्मरणों को बढ़ाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष डॉ. सी.एल. कोष्ठी ने की।

ABRSM Delegation met MHRD

ABRSM delegation has met honourable minister of HRD Sh. Prakash Javadekar ji. The delegation was led by ABRSM National Organizing Secretary Sh. Mahendra Kapoor, National General Secretary Jagdish Prasad Singhal, National Joint secretary Dr. Manoj Sinha and Dr. Anurag. The meeting was held in a very cordial atmosphere.

The following points are almost decided of course in the longer interest of the teaching community but we have to wait till these are formally announced by the government.

1. The 7th pay review committee report shall be placed in the cabinet meeting and is going to be announced very soon.
2. The anomalies of the 6th pay review committee have been almost removed and whatever left over is found shall also be eliminated. The anomalies comprise of both financial and academic anomalies.
3. The pre-2004 pension scheme (Old pension scheme) shall be at least revived to ensure the mobility / portability of faculty in between different universities / colleges.The ministry will give a very serious relook over this issue.ABRSM is very vigorously pushing this point.
4. Age of superannuation shall be 65 across all universities in India.
5. No ad-hoc / contractualization of vacancies any more. The ministry is very very particular about this aspect. They are planning a robust mechanism to practically ensure filling up of 4000 vacancies within a stipulated time interval of next one year in DU.
6. We got a definite positive hint that retrospective implementation of API-PBAS model is going to be scrapped. Off the record we are all listening that API-PBAS has been scrapped from the 7th pay package, but that is for the future. What we deliberated today again is the stake of thousands of teachers who are stuck up without getting a single promotion during last many years. This development is a clear sign of changing perceptions with in the ministry.
7. As Principals are integral part of ABRSM, we have been successful in convincing the ministry officials that the Principals after having been appointed for 5 / 10 years (peer review), they go back as Associate Professor with in the college as their appointment is not on lien. The ministry has agreed to appoint Principals on lien so that they will preserve their benefits after completing their tenures.
8. The course work for doing Ph.D. by the permanent teachers will also be covered within the tenure of the study leave.
9. One major boost against the exploitation of teachers both at school and college levels (aided institutions) is the fact that government has agreed to initiate a Direct debit Transfer Facility (DDTF) from their accounts to transfer full amount of salary to the teacher's accounts. The "cashback" implemented by these institutions shall be definitely curbed.
10. The ABRSM delegation has very strongly raised the issue of counting of past service. The ad-hoc teachers who have been working for a long time span are clearly at loss. The DU earlier used to accept this, but now it has been scrapped. The ministry has asked us to give a detailed rationale in support of this point which we shall do. Let us hope for the best if this demand is also accepted for all teachers of this country.
11. Parity of librarians, sports teachers, system analysts and other similar cadre employees has been raised. It was pointed out by the ministry that these employees are NOT directly involved in class room teaching to which we have said that they are never involved into these activities, so denying them their benefits for NO fault of theirs is not correct. The ministry has assured us to relook this issue as well.
12. Besides these, several issues relating to education policy have also been discussed, most of which have been accepted.